स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में आत्मनिर्भर बन रहा असम

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 04 – अंक : 01 – अप्रैल 2026

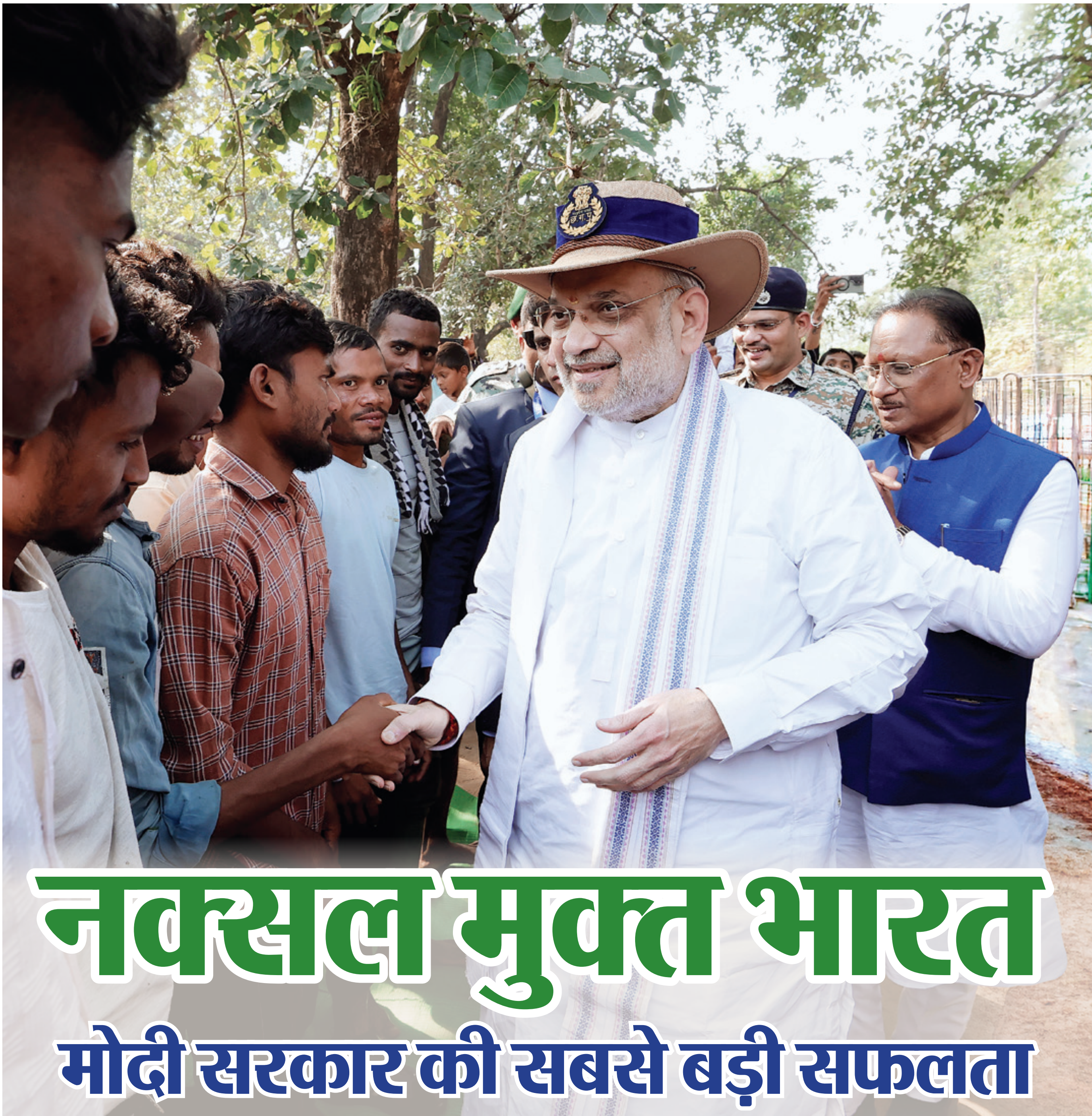

नक्सल मुक्त भारत

मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता

देश में सभी के लिए एक समान कानून के प्रति सरकार प्रतिबद्ध 13
देश के विकास का सशक्त इंजन बन रही सहकारिता 22

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
अप्रैल 2026, अंक 01, वर्ष 04

संपादक मंडल

संपादक
राजीव शर्मा

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली : 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:

MINISTRY OF COOPERATION

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

08 **आवरण कथा**

नक्सल मुक्त भारत मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता

केंद्र सरकार की ठोस रणनीति से देश नक्सल मुक्त हुआ है। भारत को नक्सल मुक्त कराना मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सफलता है।

06

अमूल डेयरी व सारस्वत सहकारी बैंक का टर्नओवर एक लाख करोड़ के पार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में निरंतर साकार होता जा रहा है। सहकारिता से जुड़े लोग जहां खुद सशक्त हो रहे हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देकर उसे मजबूत बना रहे हैं।

देश में सभी के लिए एक समान कानून के प्रति सरकार प्रतिबद्ध — 13

पिछले एक दशक में अपनाई गई ऊर्जा विविधीकरण रणनीति हर संकट में कारगर — 14

भारत टैक्सी से सारथियों के जीवन में खुशहाली, यात्रियों को भी मिली राहत — 18

असम की प्रगति समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्रदान कर रही गति — 20

जीडीपी में सहकारिता का योगदान तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य — 24

सहकारिता क्षेत्र के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती — 26

29

हजारों परिवारों के रोजगार और समृद्धि का आधार बनी सीताजाखला डेयरी कोऑपरेटिव

वामपंथी नक्सलवाद का अंत, एक ऐतिहासिक उपलब्धि

देश के समग्र विकास और विकसित भारत के निर्माण के सबसे बड़े अवरोध को मिटाते हुए सरकार ने वामपंथी नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की महत्तम उपलब्धि सरकार की ग्रामीण, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों तक विकास गति को तेज करने, वंचित वर्गों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने और पूरे देश में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने की स्पष्ट विकासमूलक दृष्टिकोण और योजनाबद्ध रणनीति के तहत सुदृढ़ कार्रवाई का ही परिणाम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2024 में जब यह घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अन्त कर दिया जायेगा, तब इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को तय समयसीमा में हासिल कर पाना बहुत दुष्कर था, लेकिन सरकार के दृढ़ निश्चय और मजबूत नेतृत्व को पाकर केंद्रीय सशस्त्र बलों ने राज्य पुलिस और स्थानीय आदिवासियों के सहयोग से इसे कर दिखाया है। इस उपलब्धि के अर्जित होने में वर्ष 2014 से सरकार के सड़क, बिजली, स्वास्थ्य व अन्य बुनियादी सुविधाओं के रूप में विकास योजनाओं को देशभर में सुदूर गांवों तक पहुंचाने का भी योगदान है।

1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू होकर, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदि राज्यों के 126 जिलों में भय, हिंसा व अशांति पैदा कर कानून-व्यवस्था को तोड़ने वाले इन नक्सलियों ने ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के भोले-भाले ग्रामीणों का जीवन नष्ट कर दिया और समाज के एक बड़े तबके को आर्थिक-सामाजिक रूप से और पीछे धकेल दिया था। लोकतंत्र और विकास के धुर विरोधी इन नक्सलियों ने आदिवासियों का बहुत शोषण किया, जिससे समाज में भय का ऐसा वातावरण तैयार हुआ कि लाखों देशवासियों के जीवन में अंधेरा छा गया, हजारों युवा गुमराह हो गए और बहुत से घर इनकी हिंसा के शिकार हो गए। इन नक्सलियों ने गांवों में स्कूल, हास्पिटल और बैंक जला दिए और उन क्षेत्रों में विकास की गति को अवरुद्ध कर लोगों को दिग्भ्रमित किया।

इन विषम परिस्थितियों में भारत सरकार ने विकास और आंतरिक सुरक्षा के इन शत्रुओं पर प्रहार कर देश के समग्र विकास के संकल्प के साथ बुनियादी विकास पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही, नक्सलवादियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार शुरू किया। बिहार में जहां, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन चक्रबांधा व ऑपरेशन भीमबर्ग चला, वहीं झारखंड में ऑपरेशन डबल बुल व ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म चलाकर इन राज्यों को नक्सलमुक्त किया। तेलंगाना व छत्तीसगढ़ की सीमा में 50 किलोमीटर लंबी और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया, जहां सैकड़ों नक्सलियों ने स्थायी कैंप बनाकर हथियारों का जखीरा और इतना अनाज इकट्ठा कर लिया था कि वे वर्षों तक शासन को चुनौती दे सकें। इसीतरह, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी सरकार ने नक्सलियों का सफाया किया है। सुरक्षाबलों ने बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ, चकरबंधा, बरमसिया और अबूझमाड़ जैसे इनके पुराने गढ़ों पर स्थायी नियंत्रण स्थापित कर नक्सलियों के आधार क्षेत्र को समाप्त कर दिया है। देश को नक्सलियों से मुक्ति मिलने से आदिवासी क्षेत्रों के साथ ही पूरे देश में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हुआ है।

जय सहकार

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी ट्रेनें और बंदरगाहों की क्षमता का विस्तार इसी का सुपरिणाम है। हाल ही में, उड़ान योजना को और विस्तार दिया है, जिसके तहत आने वाले वर्षों में छोटे-छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

सारस्वत सहकारी बैंक और अमूल द्वारा वर्ष 2025-26 में एक लाख करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर का आंकड़ा पार करना, सहकारिता की शक्ति और उसकी अपार संभावनाओं का जीवंत उदाहरण है। यह उपलब्धि न केवल सहकारी बैंकिंग और डेयरी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि इससे आत्मनिर्भर भारत की निर्माण यात्रा को भी नई ऊर्जा मिलने वाली है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और प्रभावी बनाकर किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी संस्थाओं को नई मजबूती देने के लिए मोदी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। 'सहकार से समृद्धि' हमारे संकल्प का आधार है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'मुद्रा योजना' बिना गारंटी ऋण देकर नए उद्यमियों को सशक्त बना रही है। वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है और अनौपचारिक उधारी पर निर्भरता घट रही है।

श्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने में सहकारी चीनी मिलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गन्ना किसानों को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सहयोग मिल सके। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सहकारी चीनी मिलों में हो रहे यह सुधार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं और 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

तकनीक की मदद से मछुआरों का जीवन हो रहा आसान : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सहकार जागरण टीम

मछुआरे सिर्फ समुद्र के योद्धा ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव भी हैं। तकनीक की मदद से मेहनतकश मछुआरों का जीवन आसान बनाया जा रहा है। इससे मत्स्यपालन उद्योग को फलने-फूलने का अवसर भी मिला हैं। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड में कही। मछुआरों की सुविधा के लिए उनका बीमा कराने, बंदरगाहों का विकास करने आदि पहलों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम जानते हैं कि समुद्र में उनकी गतिविधियों को मौसम का रुख बहुत प्रभावित करता है। इसे देखते हुए तकनीक के जरिए उनकी पूरी मदद की जा रही है। इससे मत्स्य क्षेत्र न केवल समृद्ध हो रहा है, बल्कि मछुआरों में कुछ नया करने का जज्बा भी पैदा हो रहा है। मत्स्य पालन और समुद्री वनस्पति के क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं। इससे हमारे मछुआरे भाई-बहन आत्मनिर्भर बन रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती व विकास में योगदान दे रहे हैं।

भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा की ताकत जब राष्ट्र निर्माण में जुड़ती है तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। राष्ट्र निर्माण के इस दायित्व को निभाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, मेरा युवा भारत यानि MY Bharat संगठन। ये संगठन देश के युवाओं को विभिन्न प्रकार की सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ रहा है। युवा इन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भागीदारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए कितना तत्पर हैं।

जल संरक्षण के संकल्प को फिर से दोहराने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 'जल संचय अभियान' ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देश-भर में करीब 50 लाख कृत्रिम जल संचयन संरचना बनाए गए हैं। अब जल संकट से निपटने के लिए गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। कहीं पुराने तालाबों की सफाई हो रही है, कहीं बरसात के जल को सहेजने के लिए प्रयास किया जा रहा हैं। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देशभर में करीब 70 हजार अमृत सरोवर बनाए गए हैं।

त्रिपुरा की जंपुई पहाड़ियों में बसे वांगमुन गांव की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि तीन हजार फीट की ऊंचाई पर बसा यह गांव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। गर्मी के दिनों में गांव के लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय करते थे। आखिरकार गांव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय किया। आज वांगमुन गांव के लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हो गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी एक अनोखी पहल देखने को मिली। यहां के किसानों ने अपने खेतों में छोटे-छोटे तालाब और गड्ढे बनाए। इससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे-धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है। इसी प्रकार तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सोख्ता बनाया। इससे गांव का जलस्तर ऊपर आया और प्रदूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। ■

वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारी संस्थाओं ने गाड़ा सफलता का झंडा

अमूल डेयरी व सारस्वत सहकारी बैंक का टर्नओवर एक लाख करोड़ के पार

▶▶ देशव्यापी मजबूत वितरण नेटवर्क से अमूल ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में निरंतर साकार होता जा रहा है। सहकारिता से जुड़े लोग जहां खुद सशक्त हो रहे हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देकर उसे मजबूत बना रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अमूल व सारस्वत सहकारी बैंक का वार्षिक टर्नओवर एक लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि सारस्वत सहकारी बैंक और अमूल द्वारा वर्ष 2025-26 में एक लाख करोड़ के वार्षिक टर्नओवर का आंकड़ा पार करना सहकारिता की शक्ति और उसकी अपार संभावनाओं का जीवंत उदाहरण है। यह उपलब्धि न केवल सहकारी बैंकिंग और डेयरी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि इससे आत्मनिर्भर भारत की निर्माण यात्रा को भी नई गति और ऊर्जा मिलने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह उपलब्धि सहकारिता मॉडल की पारदर्शिता, सामूहिकता एवं जनविश्वास की सशक्त पुष्टि करती है। यह न केवल सहकारी बैंकिंग और डेयरी क्षेत्र को नई दिशा देगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अहम योगदान देकर 'सहकार से समृद्धि' के विजन को और सुदृढ़ करेगी।

दुनिया की नंबर वन डेयरी कोऑपरेटिव अमूल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अमूल का यह कारनामा न सिर्फ भारतीय सहकारिता क्षेत्र के लिए, बल्कि दुनिया भर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक मिसाल है। अमूल ने बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अमूल फिलहाल दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, आइस्क्रीम, बटर, मिठाई समेत इसके 1200 प्रॉडक्ट तैयार करता है। अमूल की पहचान अब सिर्फ डेयरी कोऑपरेटिव के रूप में नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी के तौर पर भी है। इसकी धमक दुनिया के बाजार में भी है। इसके अलावा इसकी पहुंच भारत से बाहर करीब 50 देशों में है।

अमूल ने यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2025-26 में हासिल की है और ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में अमूल का टर्नओवर 90 हजार करोड़ रुपए था जो इस बार यानी वर्ष 2025-26 में 11 फीसदी की बढ़त के साथ एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। यह उपलब्धि न सिर्फ कंपनी की तेज ग्रोथ को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारतीय कोऑपरेटिव मॉडल आज ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के अमूल ब्रांड का कुल टर्नओवर एक लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष (2024-25) के लगभग 90 हजार करोड़ के टर्नओवर के मुकाबले 11 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। इस उपलब्धि तक पहुंचने वाला अमूल भारत का पहला एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) ब्रांड बन गया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) की ओर से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सहकारी संगठन

घोषित अमूल से लगभग 36 लाख (3.6 मिलियन) डेयरी किसान जुड़े हैं और वे ही इसकी सफलता के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। यह उपलब्धि सहकारिता की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। किसान-केंद्रित अमूल एक मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। इस मॉडल में दूध का उत्पादन करने वाले किसान ही मालिक हैं। दूध की बिक्री से होने वाला लाभ सीधे किसानों तक पहुंचता है। किसी मध्यस्थ के न होने से उन्हें दूध की अच्छी कीमत मिलती है और नियमित आय सुनिश्चित होता है।

फेडरेशन और उससे जुड़े 18 जिला दुग्ध संघ मिलकर गुजरात के 36 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिदिन लगभग 3.1 करोड़ लीटर दूध का संग्रहण और सालाना 24 अरब से अधिक उत्पाद पैकों का वितरण इसकी ठोस आपूर्ति प्रणाली को दर्शाता है। जिला दुग्ध संघ के माध्यम से लाखों छोटे-मोटे किसानों को जोड़कर अमूल ने 1,200 से अधिक प्रोडक्ट पैक्स का विशाल पोर्टफोलियो बनाया है। अमूल की सफलता की नींव उसके मजबूत और व्यापक ग्रामीण नेटवर्क में निहित है। अपने मजबूत वितरण नेटवर्क की वजह से इसकी पहुंच देश के कोने-कोने तक है। अमूल के उत्पाद पूरे देश में शहर से लेकर गांव तक हर जगह उपलब्ध होते हैं। यह मॉडल भारत को डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान दे रहा है। भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। पहले जहां दूध आयात होता था, वहीं आज अमूल न सिर्फ घरेलू मांग पूरी कर रहा है बल्कि यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में निर्यात भी बढ़ा रहा है। पिछले वर्ष अमूल ने यूरोप और अमेरिका में ताजा दुग्ध उत्पाद लॉन्च किए। यह इसे वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

जीसीएमएमएफ के चेयरमैन अशोक चौधरी के अनुसार यह उपलब्धि करोड़ों उपभोक्ताओं के विश्वास और 36 लाख डेयरी किसानों की अथक मेहनत का परिणाम है। वाइस चेयरमैन गोर्धन धमेलिया ने कहा कि यह सहकारी भावना का मील का पत्थर है। अमूल मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाकर हम आर्थिक लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट साबित कर रहे हैं। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा को नई ऊर्जा देगी। डेयरी क्षेत्र रोजगार, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमूल की सफलता अन्य सहकारी क्षेत्रों को भी प्रेरित करती है कि सही गवर्नेंस, तकनीकी अपनाव और किसान-उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की जा सकती है। ■

सारस्वत सहकारी बैंक ने स्थापित किया मील का पत्थर

सारस्वत बैंक बना एक लाख करोड़ का कारोबार करने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक

उधर, सारस्वत सहकारी बैंक ने भी एक बड़ा ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत की सबसे बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने एक वर्ष में एक लाख करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया है। बैंक ने यह उपलब्धि 6 अप्रैल 2026 को हासिल किया। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने 91,814 करोड़ का व्यवसाय किया था। सहकारिता से समृद्धि का जीवंत उदाहरण सारस्वत बैंक की यह उपलब्धि साबित करती है कि सही नेतृत्व, विश्वास और सेवा भावना से सहकारी मॉडल भी बड़े वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। 108 वर्ष पहले 1918 में स्थापित यह बैंक भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जिसने एक लाख करोड़ रुपए के मुकाम को हासिल किया है। इससे साबित होता है कि मजबूत गवर्नेंस, ग्राहक विश्वास और तकनीकी प्रगति के साथ कोऑपरेटिव मॉडल भी कमर्शियल बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशानिर्देशन में सहकारी बैंकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया गया है, जिसका लाभ भी सारस्वत बैंक ने आगे बढ़कर उठाया है। बैंक ने उत्तर भारत में भी कई नई शाखाएं खोला है जिससे कोऑपरेटिव उद्यमियों को फायदा हुआ है। बैंक के कारोबार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

बैंक का लक्ष्य अब अगले सात-आठ साल में अपने कुल वार्षिक व्यवसाय को दोगुना करते हुए दो लाख करोड़ तक पहुंचाना है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत और सहकारिता से समृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। 108 वर्ष से अधिक पुराने इस बैंक की यात्रा विश्वास, स्थिरता और निरंतर विकास की मिसाल रही है। अपनी विस्तार योजना के तहत बैंक ने कुछ समय पहले उत्तर भारत में आठ नई शाखाएं खोली हैं और आगामी महीनों में 13 और शाखाएं खोलने की योजना है। बैंक के अध्यक्ष गौतम ठाकुर ने इस उपलब्धि का श्रेय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को देते हुए कहा कि कोऑपरेटिव बैंकिंग में सुधार से बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने बैंक के शानदार वित्तीय प्रदर्शन का श्रेय बैंक के कर्मचारियों, प्रबंधन और निदेशक मंडल के संयुक्त प्रयासों को देते हुए इसे संस्थान के लिए गर्व का क्षण बताया।

नक्सल मुक्त भारत मोदी सरकार

सहकार जागरण टीम

केंद्र सरकार की ठोस रणनीति से देश नक्सल मुक्त हुआ है। भारत को नक्सल मुक्त कराना मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सफलता है। नक्सलवाद के विस्तार के लिए वामपंथी विचारधारा को जिम्मेदार करार देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीबी की वजह से नहीं बल्कि नक्सलवाद के कारण आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी फैली है। श्री शाह संसद में देश के नक्सलवाद से मुक्त होने पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में नक्सलियों ने विकास नहीं पहुंचने दिया, अब वहां घर-घर विकास हो रहा है। नक्सल प्रभावित रहे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के वर्ष 2024 में ही नक्सलमुक्त होने का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही हमने साझा रणनीति तैयार कर प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा की थी। इस लक्ष्य को हमने 31 मार्च 2026 को पूरा कर लिया। इसके लिए सरकार ने सुरक्षा घेरे में बढ़ोत्तरी की और पिछले वर्षों में देश में 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए।

वर्ष 2014 में जहां देश में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, वह सिर्फ दो जिलों में सिमट चुका है। श्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले छह वर्षों में 406 नए सीएपीएफ के कैंप बनाए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए और जवानों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें 400 बुलेट प्रूफ व ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां प्रदान की। साथ ही, जवानों के लिए पांच अस्पताल बनाए गए और कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्था दुरुस्त की गई। इसका असर यह हुआ कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 700 से अधिक नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 2218 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालयों के आदेश पर जेल की सजा दी गई। इस दौरान 4,839 लोगों ने आत्म समर्पण किया है। 'लाल आतंक की परछाई थी इसलिए बस्तर विकास से पिछड़ गया था, लाल आतंक की परछाई हट गई, अब बस्तर विकसित हो रहा है।'

- **अब लद गए नक्सली हिंसा करने वालों के दिन, जो हथियार उठायेगा, उसको हिसाब देना पड़ेगा**
- **वामपंथी उग्रवादियों ने दशकों तक जहां विकास नहीं पहुंचने दिया, वहां घर-घर हो रहा विकास**
- **वामपंथी विचारधारा की उपज है नक्सलवाद, गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, नक्सलवाद के कारण गरीबी फैली**

भारत के विकास का नया दौर

श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद हमने माओवादियों के साथ चर्चा नहीं की, बल्कि उन्हें समाप्त किया और विकास को

की सबसे बड़ी सफलता

> वामपंथी उग्रवाद ने अनगिनत युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। दशकों से, प्रतिगामी माओवादी विचारधारा का कई क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले एक दशक में, हमारी सरकार ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि विकास के लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचें, जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हम सुशासन को आगे बढ़ाने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहेंगे।
>
> **-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

आगे बढ़ाया। सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने की मंजूरी दी, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। विकास इसीलिए हो रहा है क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। छह हजार करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने लगभग 5,000 मोबाइल टावर लगाए हैं। दो अन्य योजनाओं में और आठ हजार 4 जी टावर बनाने का फैसला सरकार ने किया है। इन वर्षों में 1804 बैंक शाखाएं नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में खुली हैं, 1321 एटीएम खुले हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6025 डाकघर खुले।

इस दौरान आठ सौ करोड़ रुपए की लागत से 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय, 46 आईटीआई, 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर और 16 कौशल विकास केंद्र बनाए गए। सिविक प्रोग्राम में 212 करोड़ के कार्य किए गए, जो स्वास्थ्य शिविर और दवाओं से जुड़े हुए हैं। सरकार ने जनजाति युवा एक्सचेंज

- **आदिवासियों का शोषण करने वाले नक्सली लोकतंत्र के घोर विरोधी**
- **स्टेट, गवर्नेंस, संविधान और सुरक्षा का वैक्यूम खड़ा कर रक्तपात करना ही वामपंथी विचारधारा का उद्देश्य**
- **नक्सलियों ने गांवों में स्कूल, दवाखाने और बैंक जलाए, लोगों को बरगलाया, फिर बोले- विकास नहीं पहुंचा**
- **भगवान बिरसा मुंडा, शहीद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस के बजाए 'माओ' को माना अपना आदर्श**
- **सत्ता के समर्थन के बिना देश के बीचों-बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं था**

गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, नक्सलवाद के कारण गरीबी फैली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है। उन्होंने कहा कि माओवादी और नक्सली हिंसा करने वालों के दिन अब लद गए हैं। पंचायत के नक्सल मुक्त होते ही उस गांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य अब हर गांव में पहुंच चुका है, वहां पंचायत बन चुकी है। वामपंथी उग्रवादियों ने सालों तक उस क्षेत्र में विकास को पहुंचने नहीं दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवाकाल में वहां घर-घर विकास पहुंच रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद गरीबी के कारण नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में वर्षों तक गरीबी रही। नक्सलियों ने पूरे रेड कॉरिडोर को इसीलिए चुना था क्योंकि वहां राज्य की पहुंच कम थी। भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए गए। उन्होंने प्रतिपक्ष से सवाल किया कि जो आदिवासी देश की आजादी से पहले भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती, मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था, वह आदिवासी 1970 आते-आते माओ को अपना हीरो कैसे मानने लगा ? उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने विकास योजनाओं को रोकने का काम किया और 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर उनका अधिकार छीन लिया।

के कार्यक्रम भी बनाए। सुरक्षा के लिए राज्यों की सहायता के लिए एसआरई लेकर आए जिसमें 10 साल में तीन हजार करोड़ दिया। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए और इसमें पांच हजार करोड़ दिया।

पिछले 12 वर्षों के दौरान पूरे देश के हर गरीब को घर, गैस, पीने का पानी, पांच लाख तक का बीमा और पांच किलो मुफ्त अनाज मिला, लेकिन बस्तर वाले छूट गए थे क्योंकि लाल आतंक की परछाई के कारण वहां विकास नहीं पहुंचा था। लेकिन, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और वहां हर गांव में स्कूल बनाने और राशन की दुकान खोलने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इस दौरान कई वर्षों पुरानी समस्याओं का निराकरण हुआ है, धारा 370 और 35A हट गई और श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) बन चुका है और विधायी मंडलों में मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मैंने बहुत से बुद्धिजीवियों के आर्टिकल्स पढ़े जो नक्सलियों के मानव अधिकार की बात कर रहे थे, उनमें से एक भी आर्टिकल उस मां के लिए नहीं था जिसके बच्चे को नक्सली जबरदस्ती उठा ले गए या उन शहीदों की विधवाओं के लिए जिनको नक्सालियों ने मारा।

नक्सलमुक्त बनाने में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग अहम

श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार डरने वाली नहीं, बल्कि सबके साथ न्याय करने वाली संवेदनशील सरकार है। हम सभी समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना चाहतें हैं। हमारी सरकार ने हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की है। सरकार की पॉलिसी है कि चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, लेकिन जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है और जो भी हथियार उठाएगा, उसे हिसाब चुकता करना पड़ेगा। श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि देश के किसी भी कोने में चाहे कश्मीर हो, उत्तर पूर्व हो, या वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र हो, गैरकानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो वार्ता करना चाहता है, उसके साथ वार्ता और जो हमारे जवानों, किसानों, आदिवासियों, बच्चों पर गोली चलाता है, उसका जवाब गोली से देना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि देश को नक्सल मुक्त करने के लिए हमने संवाद, सुरक्षा और समन्वय को बढ़ावा दिया है। राज्यों के साथ मिलकर गवर्नमेंट, गवर्नेंस और पुलिसिंग में सुधार किया है। इसके लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का सटीक उपयोग किया जा रहा है।

श्री शाह ने संसद में कहा कि सरकार ने 'लाभप्रद पुनर्वास पॉलिसी' अपनाया है, जिसमें आत्मसमर्पण की प्रोत्साहन राशि 50,000 घोषित की गई है। सामूहिक सरेंडर

पिछले वर्षों में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण काम पूरे किए

श्री शाह ने कहा कि आजादी के वक्त से देश की जनता जो कई सारे बड़े काम चाहती थी, वह सभी काम पिछले 12 वर्षों में पूरे हुए हैं और ये वर्ष देश के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने, युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और देश के लिए अनुपयोगी नीतियों को दरकिनार करने के लिए इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। इनमें सबसे अधिक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले के रूप में नक्सलमुक्त भारत सबसे अहम है।

माओवादी घटनाएं

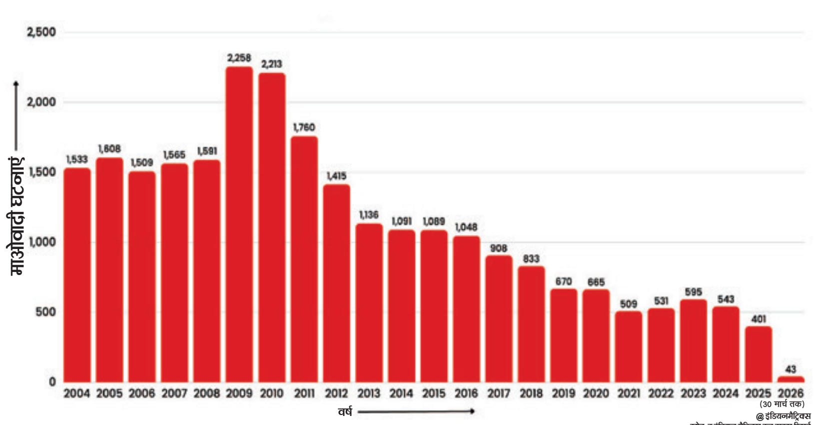

करने पर यह राशि दोगुना कर दी जाती है। सरकार की ओर से सबको मोबाइल और हथियार जमा कराने पर और मुआवजा दिया गया है और पुनर्वास के लिए तीन वर्षों तक उन्हें 10 हजार रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। साथ ही, पुनर्वासन केंद्र पर कौशल प्रशिक्षण व टूल किट का वितरण किया जा रहा है और सरकार ने सरेंडर कर मुख्यधारा में आने वाले सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना की गिफ्ट दी है। इनकी नौकरी और रोजगार के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। इनके बच्चों के लिए बारहवीं तक की शिक्षा मुफ्त की गई है। सरकार ने महिलाओं को दो लाख रुपए और पुरुषों को पांच लाख रुपए के ऋण की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कहा कि हम बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम के माध्यम से संस्कृति और खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका असर यह है कि एक लाख 20 हजार कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भागीदारी की और पांच लाख 50 हजार आदिवासी खेले हैं।

नक्सलवाद का मूल कारण है वामपंथी विचारधारा

नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं, बल्कि यही वामपंथी विचारधारा है, जिसे तत्कालीन सरकार ने स्वीकार भी किया था। श्री शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वयं इसे स्वीकार किया था कि कश्मीर और नॉर्थईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा के

> "नक्सलमुक्त भारत जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय हमारे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों, राज्य पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के जवानों और स्थानीय आदिवासियों को जाता है। वामपंथी उग्रवाद के समाप्त होने में जनता का भी बड़ा योगदान है।"
>
> **श्री अमित शाह**
>
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

सामने सबसे बड़ी समस्या हथियारबंद माओवादी हैं। इन उग्रवादियों और इनके समर्थकों ने भोले-भाले आदिवासियों के सामने एक गलत प्रकार का नेरेटिव रखा था कि वे उनके अधिकारों और उन्हे न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि जिन्होंने भी नक्सलियों का समर्थन किया है, वे सभी इस पाप के उतने ही भागीदार हैं जितना कि बंदूक लेकर घूमने वाले हैं। इन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश के तीन ज़िलों सहित 12 राज्यों में पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा था। श्री शाह ने कहा कि इन क्षेत्रों में 12 करोड़ लोग सालों तक गरीबी में जीते रहे और 20,000 युवा मारे गए, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि इस विचारधारा का विकास और विकास की मांग से कोई लेना देना नहीं है और न ही इनका लोकतंत्र पर ही कोई विश्वास है।

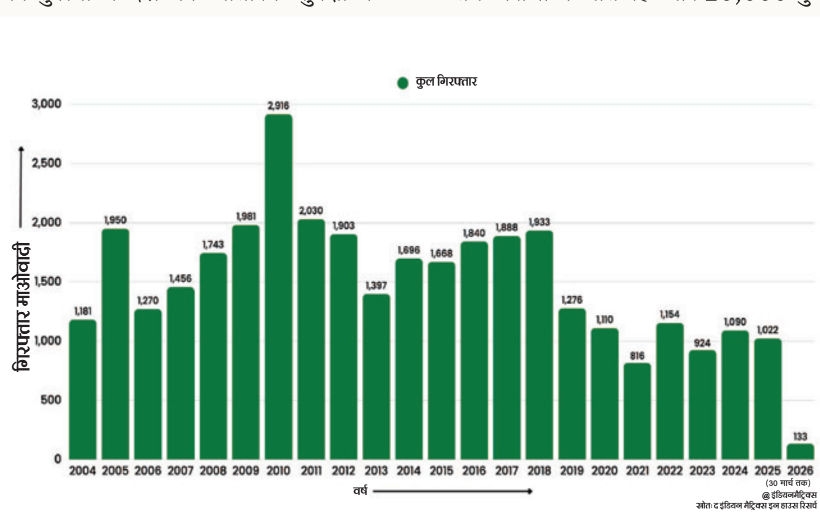

जनजातीय क्षेत्रों में विकास पर सरकार का फोकस

भारत सरकार के सुदृढ़ रणनीति और देश को नक्सली हिंसा की पीड़ा से मुक्त कराने के संकल्प का ही परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में ही लगभग 4,800 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया और 2,200 से अधिक नक्सली गिरफ्तार किये गए। वहीं, सरकार को चुनौती देने वाले 700 से अधिक नक्सलियों को निष्क्रिय कर दिया है और इसने माओवादी सैन्य क्षमता की कमर तोड़ दी है। तिरुपति से पशुपति तक के 180 से अधिक जिलों में फैले रेड कॉरिडोर के भौगोलिक दायरे में फैले नक्सलियों का प्रभुत्व नष्ट हो चुका है और पूर्व में प्रशासन-विहीन रहे इन क्षेत्रों में राज व्यवस्था फिर से स्थापित हो चुकी है। इन क्षेत्रों में शासन-सत्ता की पुनर्स्थापना लाखों ग्रामीणों एवं आदिवासियों को नक्सलियों के दमनकारी नियंत्रण से मुक्ति और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की बड़ी चुनौती पर विजय का प्रमाण है। देश को 'नक्सल-मुक्त' घोषित किया जाना आंतरिक सुरक्षा की इस बड़ी चुनौती पर एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है।

नक्सल मुक्त क्षेत्र में होगा समग्र समावेशी विकास

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह का भारत को नक्सल-मुक्त घोषित करना एक ऐतिहासिक रणनीतिक उपलब्धि है। सशस्त्र नक्सली आंदोलन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है और देश ने इस चुनौती पर बड़ी जीत हासिल की है। अब रेड कॉरिडोर के अशांत, अविकसित और भयाक्रांत रहे लोगों और इस समूचे क्षेत्र को विकसित गलियारे के रूप में रूपांतरित करने पर सरकार का फोकस है। इन क्षेत्रों का समग्र विकास, सड़क, बिजली, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से इस पूरे कोरिडोर में स्थायी शांति की स्थापना और सार्थक लोकतांत्रिक सहभागिता सुनिश्चित करके सरकार में बदलाव की मुहिम को तेज कर रही है। घने जंगली इलाकों में भी सड़क संपर्क बढ़ाया जा रहा है और मोबाइल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। संचार माध्यमों के विस्तार के जरिए सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत कर रही है और आदिवासी इलाकों में भी सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रसार हो रहा है। सरकार ने इन क्षेत्रों में 628 सुदृढ़ और अत्याधुनिक तकनीक से लैश पुलिस थानों के निर्माण किया है और रात के घने अंधेरे में भी उतरने योग्य 68 हेलीपैडों को स्थापित किया है। इसने सुरक्षा बलों को बारूदी सुरंगों को निष्प्रभावी करने और कुछ ही मिनटों में किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने में सक्षम बनाया है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के इस तेज विस्तार ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में प्रभावी बदलाव किया है। आदिवासी क्षेत्रों तक लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाकर और आकर्षक पुनर्वास विकल्प प्रदान करके सरकार ने माओवादी नक्सली क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों का

समर्थन और विश्वास हासिल किया है, जिससे नक्सली नासूर को नष्ट करने में स्थानीय लोगों का सहयोग सुनिश्चित हुआ। इसके साथ ही 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा का तीव्र विस्तार किया गया। वहीं राज्य की 'रोशनी' योजना ने वंचित युवाओं को रोजगार-संबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में भागीदार बनाया है। केंद्र सरकार की उच्च प्रोत्साहन वाली आत्मसमर्पण नीतियों के समर्थन से पिछले एक दशक में 8,000 से अधिक उग्रवादियों ने हिंसा का मार्ग त्याग कर आत्मसमर्पण करके सरकार की योजनाओं का लाभ अर्जित किया है। इसप्रकार, सरकार की सटीक रणनीति और ठोस कार्रवाई ने देश को नक्सल मुक्त बनाने में सफलता प्रदान की है और समग्र समावेशी विकास का आधार तैयार किया है।

सत्ता के समर्थन के बिना रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं था

श्री शाह ने कहा कि 1970 के दशक में नक्सलवाद की शुरूआत नक्सलबाड़ी और बंगाल से हुई, जहां एक ही वर्ष में 3620 हिंसक घटनाएं हुईं। 1980 का दशक आते-आते पीपल्स वॉर ग्रुप बन गया और फिर यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यों में फैला और 1990 के दशक में वामपंथी विचारधारा सिकुड़ती गई और उग्रवादी गुटों और वामपंथी पार्टियों में विलय शुरू हुआ। 2004 में दो प्रमुख गुट मिल गए और सीपीआई माओवादी का गठन किया। देश के 12 राज्यों और 17 प्रतिशत भूक्षेत्र और 10 प्रतिशत ज्यादा आबादी में इनका विस्तार आखिर कैसे

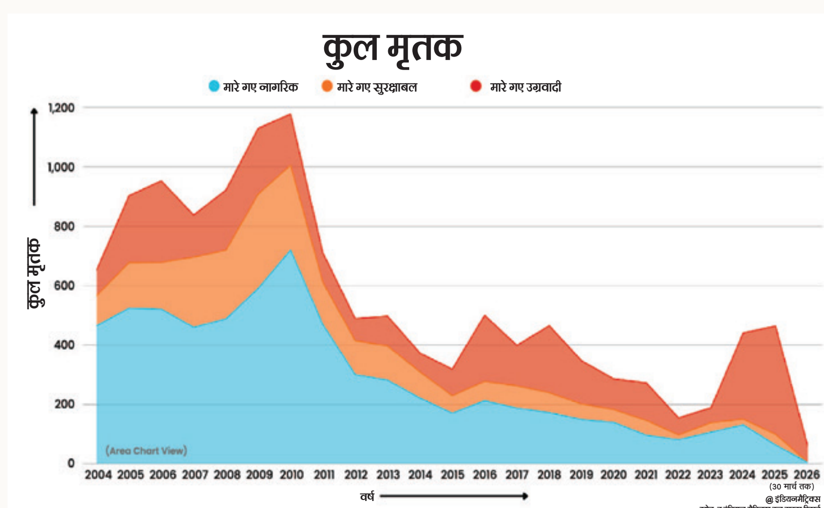

हुआ। श्री शाह ने कहा कि सत्ता के समर्थन के बगैर देश के बीचो-बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं था। ■

देश में सभी के लिए एक समान कानून के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

सहकार जागरण टीम

देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रति प्रतिबद्ध है। यह बात केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने पर कही। यूसीसी भारत में सभी धर्मों और समुदायों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करने का प्रस्ताव है। यह धर्म आधारित अलग-अलग कानूनों को समाप्त कर सभी के लिए एक समान नियम बनाने का लक्ष्य रखता है, जो समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा।

वर्तमान में विभिन्न धर्मों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी) के लोग विवाह, तलाक, और संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए अपने व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं। यूसीसी के तहत ये सभी मामले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में सुधार, विशेषकर महिलाओं को समानता और अधिकार देना, साथ ही धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है, जहां पुर्तगाली काल से ही समान नागरिक संहिता लागू है। गुजरात के पहले उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया था। श्री अमित शाह ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि देश तुष्टिकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून से चले। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत में सभी धर्मों और समुदायों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करने का प्रस्ताव है। यह धर्म आधारित अलग-अलग कानूनों को समाप्त कर सभी के लिए एक समान नियम बनाने का लक्ष्य रखता है। इससे समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता के तहत भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों के अनुयायी विवाह, तलाक, और संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि इस कानून को लागू करके ही सही मायने में समाज में समानता व न्याय की स्थापना हो सकती है और सरकार सभी को न्याय व सबके साथ समान व्यवहार करने को प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म, मत, पंथ व संप्रदाय का हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में वह समान है। एक समान कानून लागू करने से जहां सामाजिक समरसता बढ़ेगी, वहीं राष्ट्रीय एकता व अखंडता और मजबूत होगी। इसलिए समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का संकल्प है कि पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के इसे लागू किया जाए और सभी नागरिक इसके दायरे में आएं। ■

उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई

पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पिछले एक दशक में अपनाई गई ऊर्जा विविधीकरण रणनीति हर संकट में कारगर

सहकार जागरण टीम

मानवता और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट है। भारत का प्रयास है कि दुनिया में तनाव कम हो और शत्रुता खत्म हो। युद्ध जीवन को खतरे में डालता है और मानवता के खिलाफ होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद को संबोधित करते हुए यह विचार प्रगट किया। इस युद्ध के कारण उत्पन्न कठिन वैश्विक परिस्थितियों के लंबे समय तक बनी रहने की संभावना जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब इस देश की हर सरकार और हर नागरिक एक साथ चलेंगे, तब हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही हमारी पहचान है और यही हमारी शक्ति है। चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर हम दुनिया में अमन-चैन कायम रख सकते हैं।

ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में अपनाई गई ऊर्जा विविधीकरण रणनीति वर्तमान संकट में कारगर साबित हुई है। भारत ने पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा आयात के अपने स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। इससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो गई है। ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में पिछले एक दशक में उठाए गए कदम अब और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। भारत के पास आज 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है और तेल कंपनियों के अलग-अलग भंडारों के अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक का भंडार बनाने का कार्य जारी है। दुनिया में शांति-व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख देशों के साथ बातचीत कर यह तय किया जा रहा है कि ऊर्जा की आपूर्ति बाधित न हो।

भारत ने पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा आयात के अपने स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक बढ़ाया, जिससे किसी एक क्षेत्र पर हमारी निर्भरता घटी

प्रधानमंत्री ने भारत के घरेलू ऊर्जा परिवर्तन पर प्रकाश डाला। इथेनॉल मिश्रण में हुई असाधारण प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यह एक दशक पहले मात्र 1-1.5 प्रतिशत से बढ़कर आज लगभग 20 प्रतिशत हो गया है। इससे तेल आयात में प्रति वर्ष लगभग साढ़े चार करोड़ बैरल की कमी आई है। रेलवे के विद्युतीकरण से प्रति वर्ष लगभग 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हुई है।

ऊर्जा को आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ और पश्चिम एशिया को वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं का एक प्रमुख स्रोत बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान संकट विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती बन गया है। लेकिन सरकार और उद्योग के संयुक्त प्रयासों से हम इन परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होंगे। भारतीय कृषि को बाहरी झटकों से बचाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले दशक में छह नए यूरिया संयंत्र चालू किए गए हैं। इससे वार्षिक उत्पादन क्षमता में 76 लाख मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि हुई है। डीएपी और एनपीकेएस उर्वरकों का घरेलू उत्पादन लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है और उर्वरक आयात के स्रोतों में विविधता लाई गई है।

मेड-इन-इंडिया नैनो यूरिया जैसे नवोन्मेषणों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और डीजल

पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए पीएम-कुसुम योजना के तहत 22 लाख से अधिक सौर पंपों के वितरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर के सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और भारत ने लगातार दूसरे वर्ष 100 करोड़ टन कोयले के उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति से सरकार की तैयारियों को अत्यधिक मजबूती मिली है। भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा अब नवीकरणीय स्रोतों से आता है और देश की कुल नवीकरणीय क्षमता 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है। अकेले सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 11 वर्षों में लगभग 3 गीगावाट से बढ़कर 140 गीगावाट हो गई है, लगभग 40 लाख रूफटॉप सौर पैनल लगाए गए हैं। गोबर्धन योजना के तहत 200 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र अब चालू हैं और परमाणु ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही एक नई स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना अगले पांच वर्षों में 1,500 मेगावाट क्षमता जोड़ेगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हर संकट किसी भी राष्ट्र के संकल्प और उसके प्रयासों की परीक्षा लेता है। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए पिछले 11 वर्षों के दौरान दूरदर्शी निर्णय लिए गए हैं। भारत ने ऐसे ही संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडार बनाने को प्राथमिकता दी है। तेल कंपनियों के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

किसी एक ईंधन स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की सरकार की रणनीति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने घरेलू गैस आपूर्ति के लिए एलपीजी के साथ-साथ पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पर दिए जा रहे जोर को रेखांकित किया और बताया कि पिछले एक दशक में पीएनजी कनेक्शनों पर अभूतपूर्व कार्य किया गया है। देश के भीतर एलपीजी के घरेलू उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास हर क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता को न्यूनतम करना रहा है। सरकार ने मेड-इन-इंडिया जहाज बनाने के लिए लगभग 70 हजार करोड़ रुपए का एक मिशन शुरू किया है। इसके साथ ही जहाज निर्माण, जहाज तोड़ने (शिप ब्रेकिंग) और उनके रखरखाव एवं मरम्मत (ओवरहॉलिंग) की क्षमताओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाया गया है। अब देश अपनी अधिकांश सैन्य आवश्यकताओं और हथियारों का निर्माण घरेलू स्तर पर ही कर रहा है। इसके अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं के लिए घरेलू एपीआई इकोसिस्टम बनाने और 'रेयर अर्थ मिनरल्स' के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

कृषि क्षेत्र पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार मजबूती के साथ देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। हम किसी भी वैश्विक संकट का बोझ अपने किसानों के कंधों पर नहीं पड़ने देंगे।■

नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा भारतः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

‘गल्फ’ से लेकर ‘ग्लोबल वेस्ट’ तक और ‘ग्लोबल साउथ’ से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत के अभूतपूर्व संबंध

सहकार जागरण टीम

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों को पीछे छोड़कर आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में ये विचार व्यक्त किया। बटी हुई वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत की कूटनीतिक पहुंच के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, और ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए हैं और खुद को सभी के लिए भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया है।

‘जिसका आकलन किया जाता है, उसे प्रबंधित किया जाता है’ कहावत को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसका आकलन किया जाता है, उसमें सुधार भी होता है और अंततः वह परिवर्तित भी होता है। अब भारत में राजमार्ग निर्माण की गति 11-12 किमी/दिन से बढ़कर लगभग 30 किमी/दिन हो गई है। बंदरगाहों पर जहाजों का टर्नअराउंड समय 5-6 दिन से घटकर दो दिन से भी कम हो गया है। पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 400-500 से बढ़कर दो लाख से अधिक हो गई है। एमबीबीएस सीटें 50-55 हजार से बढ़कर 1.25 लाख से अधिक हो गई हैं; बैंक खातों की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ से अधिक हो गई है (जिनमें 55 करोड़ जन धन खाते शामिल हैं); और हवाई अड्डों की संख्या 160 से अधिक हो गई है। ‘आज, भारत फास्ट ट्रैक पर है, आज, संकल्प को सिद्धियों में बदल रहे हैं।’

वर्तमान में जारी महत्वपूर्ण बदलावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस असम में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही है। ओडिशा में सेमीकंडक्टर से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक अनेक क्षेत्रों का विकास हो रहा है। बिहार में पिछले दस साल में पांच से अधिक नए पुलों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश मोबाइल फोन निर्माण के एक वैश्विक केंद्र में बदल हो चुका है। भारत अतीत में उत्पन्न हुए विकास असंतुलनों को भविष्य के अवसरों में बदल रहा है। पश्चिम बंगाल को अतीत में संस्कृति, शिक्षा, उद्योग और व्यापार का केंद्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निवेश किया है। देश हित को दल हित से ऊपर रखना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र और उसका विकास राजनीति से ऊपर होता है। देश हित को सबसे ऊपर रखने की प्रेरणा भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएगी। विकसित भारत बनाने के लिए देश तेज गति से काम कर रहा है।■

गुवाहाटी में विकास कार्यों का लोकार्पण कर श्री अमित शाह ने कहा

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में आत्मनिर्भर बन रहा असम

सहकार जागरण टीम

'यह बहुत जरूरी है कि हमारे देश में मेडिकल शिक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था हो और हर प्रकार के क्रिटिकल रोग के लिए युवाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, जहां से रिसर्च करके वे न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के मरीजों की सेवा कर सकें।' केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को असम सरकार के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के दौरान गुवाहाटी में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि यह कार्यक्रम न सिर्फ असम, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक दशक पहले पूरे पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा था, वहीं असम के मुख्यमंत्री के रूप में श्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की स्वास्थ्य

- **क्रिटिकल स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हब बना असम, प्रोटॉन कैंसर थेरेपी जैसी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना**
- **प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने असम के स्वास्थ्य बजट को 4,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपए किया**

व्यवस्था को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने में सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों में सरकार के साथ समाज की शक्ति को भी जोड़ा है। इस दौरान राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कि गरीब परिवारों के बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। साथ ही, ढेर सारे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा, यहां अनेक प्रकार के क्रिटिकल रोगों के लिए देश की सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का निर्माण किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में असम को एक समृद्ध राज्य बनाने पर फोकस

श्री शाह ने कहा कि प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को जनता की सेवा के लिए अर्पित किया। इसे लगभग 675 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया

है। इसके साथ ही श्री शाह ने 135 करोड़ रुपए की लागत से गोलाघाट कैंसर सेंटर, 135 करोड़ रुपए की लागत से तिनसुकिया कैंसर सेंटर, 220 करोड़ रुपए की लागत से डिफू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 284 करोड़ रुपए की लागत से बरपेटा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 310 करोड़ रुपए की लागत से जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 218 करोड़ रुपए की लागत से सिक्स माइल स्वास्थ्य भवन का और 115 करोड़ रुपए की लागत से अभयापुरी जिला अस्पताल का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में स्वास्थ्य क्षेत्र में असम को एक समृद्ध राज्य बनाने का राज्य सरकार का यह प्रयास स्वास्थ्य क्षेत्र में असम को आत्मनिर्भर बनाने वाला सिद्ध होगा।

श्री शाह ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री असम को ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं कि एक भी मरीज को असम से बाहर न जाना पड़े। साथ ही, बंगाल और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के गरीब मरीज भी असम में आकर इलाज करा सकें। उन्होंने बराक वैली, उत्तर असम, सेंट्रल असम, लोअर असम सहित असम के हर हिस्से में कैंसर से लेकर सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया है। श्री शाह ने कहा कि अब पूर्वोत्तर के मरीजों को चेन्नई, मुंबई, कर्नाटक या दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें अपने नजदीक के सरकारी अस्पताल में ही इलाज की सारी सुविधा सुलभ होगी।

पूर्ववर्ती सरकार के स्वस्थ असम बनाने के संकल्प के प्रति उदासीनता बरतने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए श्री शाह ने कहा कि 10 वर्ष पहले की सरकार ने असम के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज वे गर्व से कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार ने असम को स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य शिक्षा में स्वावलंबी बनाने का काम पूरा किया है। श्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार में असम का स्वास्थ्य बजट 4,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने बजट को जमीनी स्तर पर खर्च करने का काम किया है। जहां, असम में पहले छह मेडिकल कॉलेज थे, वहां अब 14 बन चुके हैं और 10 और बनने हैं, जिससे राज्य में कुल मिलाकर 24 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटें भी पहले की 726 से बढ़कर 14 कालेजों में ही ही 1825 सीटें हो गई हैं।

सरकार ने युवाओं के लिए कई क्षेत्रों में नए क्षितिज खोले

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के लिए कई क्षेत्रों में नए क्षितिज खोले हैं। उनका स्वप्न है कि एक ऐसा मंच बने, जहां खड़े होकर भारत का युवा विश्व के युवाओं से प्रतिस्पर्धा कर सके। अंतरिक्ष, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, एआई, 5जी के बाद 6जी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर आदि इमर्जिंग सेक्टर आने वाले 25 वर्षों तक विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। भारत आज इनमें फाउंडर मेंबर बन चुका है। देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इन सभी विधाओं के लिए शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े 'एआई समिट' का दिल्ली में आयोजित होना और उसमें 22 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और 80 देशों की कंपनियों के टॉप सीईओ का शामिल होना सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। श्री शाह ने कहा कि असम में पहली बार 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर कारखाना लगा है।

गंभीर बीमारियों के इलाज की बढ़ती सुविधाएं

असम में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की बढ़ती सुविधाओं पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार में असम कैंसर सहित क्रिटिकल स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हब बन चुका है। राज्य में कैंसर केयर के पहले दो अस्पताल थे, जिसे अब 17 अस्पतालों के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले स्वास्थ्य बीमा की कोई योजना नहीं थी और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की और फिर असम सरकार ने भी अलग से अटल अमृत अभियान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इतना ही नहीं, लोगों के महंगे इलाज के लिए असम सरकार ने उद्योग जगत से सीएसआर फंड इकट्ठा किया है। इससे इलाज के खर्च का भुगतान राज्य सरकार करती है और गरीब को महंगे इलाज में भी कुछ नहीं देना पड़ता। श्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि गरीबों का संपूर्ण इलाज हो जाए और उन परिवारों की कमाई बीमारी में नष्ट न हो और न ही बीमारी से ऋण का बोझ उन पर पड़े। हम चाहते हैं कि गरीब परिवारों के होनहार भी डॉक्टर बन सकें और हमारी सरकार ने शासन के इसी अप्रोच को यहां लागू किया है। ■

'सारथियों की कहानी, उन्ही की जुबानी'

भारत टैक्सी से सारथियों के जीवन में खुशहाली, यात्रियों को भी मिली राहत

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन निरंतर धरातल पर उतर रहा है और अपने उद्देश्य को हासिल कर रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर चंद माह पहले सहकारिता मॉडल पर शुरु भारत टैक्सी सेवा से जुड़े ड्राइवर और कस्टमर दोनों संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। इस कंपनी से जुड़कर मालिक की भूमिका में आए ड्राइवर, जिन्हें सारथी कहा जाता है, इसमें अपना और अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं और संतुष्टि जता रहे हैं।

मेरा नाम एस लाल हैं। मैं लंबे समय से टैक्सी चला रहा हूं। मार्केट में ऐप आधारित निजी कंपनियों के आने पर उनके साथ काम किया। लेकिन अब हमारे गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हमें भारत टैक्सी के रूप में एक उपहार प्रदान किया है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। इसमें चालकों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड की भी व्यवस्था है। हाल ही में मुझे 900 और 500 रुपए का दो सुपर सारथी अवार्ड मिला है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का भी वादा किया गया है। इससे हमें बहुत उम्मीद है और हम अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। पहले एक सिलेंडर सीएनजी से 10 से 12 हजार रुपए का काम होता था और 9 से 10 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट मिलता था, लेकिन भारत टैक्सी में हमें 15 से 20 रुपए का रेट मिलता है। क्योंकि इसमें कमीशन नहीं कटता है। इससे हमारी इनकम बढ़ गई है।

मेरा नाम नरेश कुमार है। भारत टैक्सी से जुड़कर मुझे बहुत लाभ हुआ है। इस क्षेत्र में सक्रिय निजी टैक्सी कंपनियों के मुकाबले दिन भर में मैं अच्छी कमाई कर लेता हूं। भारत सरकार और मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। भारत टैक्सी का साथ मिलने से मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं दिल्ली में हर जगह टैक्सी चलाता हूं, परिवहन मोर्चा का सदस्य भी हूं। मैंने अपने संगठन में सभी से भारत टैक्सी का ऐप यूज करने के लिए कहा है। मैं अन्य लोगों से भी अपील करता हूं कि वे भी भारत टैक्सी से जुड़ें और इसकी सेवा लें, क्योंकि यह अन्य टैक्सी कंपनियों के मुकाबले लाभदायक है और अच्छी सेवा दे रही है।

मेरा नाम रमेश भाई परमार है। पहले बाजार में सक्रिय निजी टैक्सी कंपनियों में हम मात्र एक ड्राइवर थे, लेकिन भारत टैक्सी के साथ जुड़कर हम इसके मालिक हो गए। अब हमें सारथी कहा जाता है। इससे हमारी प्रतिष्ठा और गरिमा भी बढ़ गई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर शुरू यह स्वदेशी टैक्सी सेवा सबके लिए फायदेमंद है। इसमें ड्राइवरों के साथ ग्राहकों की भी सुविधा व सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। इससे जहां ड्राइवरों की कमाई बढ़ गई, वहीं ग्राहकों को भी उचित दर पर आरामदेह सेवा उपलब्ध हो रही है। इसके साथ काम करने से ड्राइवरों व उनके परिवार का भविष्य उज्ज्वल रहेगा।

हम ड्राइवरों को लंबे समय से भारत टैक्सी जैसी कंपनी का इंतजार था, क्योंकि अन्य निजी टैक्सी कंपनियां हमारा शोषण करती थीं। ये कंपनियां हमें हमारा पूरा पारिश्रमिक नहीं देती थीं। किराए के रूप में होने वाली हमारी कमाई का अधिकतर हिस्सा कमीशन के नाम पर अपने पास रख लेती थीं। लेकिन अब भारत टैक्सी के आने से शोषण से छुटकारा मिल गया है। कस्टमर से मिलने वाला पूरा किराया सीधे हमारे खाते में जमा हो जाता है। अब कोई बिचौलिया नहीं रहा। हम लोग भारत टैक्सी से जुड़कर इसके मालिक हो गए और अब हमारी इनकम धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। हम इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं।

मेरा नाम रमेश है। मैं लंबे समय से टैक्सी चला रहा हूं। लेकिन भारत टैक्सी से जल्द ही जुड़ा हूं। अब तक इससे जुड़कर 81 राइड किए हैं और 35 हजार की कमाई कर चुका हूं। इसमें बहुत अच्छी राइड मिलती है। अन्य टैक्सी कंपनियों के मुकाबले रेट अधिक होने के कारण किराया भी ज्यादा मिलता है। भारत टैक्सी से जुड़कर मैं बहुत संतुष्ट हूं और कमाई बढ़ने से मेरा परिवार भी खुश है। मैं अन्य टैक्सी ड्राइवरों से भी कहना चाहता हूं कि वे भी इस कंपनी से जुड़कर उसके मालिक बनें। इसमें ग्राहक से मिलने वाले किराए में किसी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। पूरा किराया अपना होता है।

मेरा नाम अजयकुमार गुप्ता है। मैं अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन का प्रेसीडेंट हूं। भारत टैक्सी का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। इसकी सेवा लेने वाले ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी बहुत उत्साहवर्धक है। क्योंकि उन्हें अन्य निजी टैक्सी कंपनियों की अपेक्षा भारत टैक्सी के जरिए संतोषजनक और सस्ती सेवा मिल रही है। इसमें सारथी भाइयों को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। पूरा किराया टैक्सी ड्राइवर की जेब में जाता है। इस कंपनी के मालिक भी सभी सारथी भाई हैं। सभी को इस स्वदेशी कंपनी से जुड़ना चाहिए। मैं सभी टैक्सी ड्राइवरों से अपील करता हूं कि वे भारत टैक्सी से जुड़ें और इसका ऐप डाउनलोड करें। इस टैक्सी कंपनी को लॉन्च करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री का आभार जताता हूं।

मेरा नाम रैवर वंदराज है। मैं भारत टैक्सी से जुड़कर बहुत संतुष्ट हूं। क्योंकि इस कंपनी के साथ जुड़ने से मेरी कमाई बढ़ गई है। अब मैं अपने परिवार की देखरेख अच्छी तरह से कर पा रहा हूं। इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का प्रयास बहुत सराहनीय है। पहले मुझे रेफरल कोड का पता नहीं था। मेरे दोस्तों ने मुझे इसकी जानकारी दी और अब मुझे इससे लाभ हो रहा है। मैंने अपने रेफरल कोड के जरिए अपने कई दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों को भारत टैक्सी की ऐप डाउनलोड कराई है। अब अगर मेरा मित्र, रिश्तेदार या कोई अन्य इसकी सेवा लेता है और मेरा रेफरल कोड देता है, तो मुझे 100 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलता है। इससे मेरी कमाई में इजाफा हो गया है। इससे मैं बहुत खुश हूं।

मेरा नाम प्रवीण ठाकोर है। मैं पहले बिग बास्केट में जॉब करता था। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद इससे मेरा मन ऊबने लगा और मैं कोई और काम करने के बारे में सोचने लगा। इसी दौरान मैंने एक टैक्सी खरीद ली और निजी टैक्सी कंपनियों के साथ मिलकर चलाने लगा। एक-डेढ़ साल चलाने के बाद मुझे लगा कि इनके साथ काम करना फायदेमंद नहीं है। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने मुझे भारत टैक्सी के बारे में बताया और मैं इससे जुड़ गया। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसमें रेट अधिक मिलता है। इसका अनुभव बहुत संतोषजनक है। अब हम इसी के साथ आगे बढेंगे और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इससे जुड़कर हमारी कमाई बढ़ गई है और हमारा परिवार खुश है।

मेरा नाम नरेंदर है। सहकार मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो मैं इससे जुड़ गया। मैं तीन-चार महीने से इसके साथ कार्य कर रहा हूं। इससे मेरा इनकम बढ़ गया है। इस कंपनी के साथ सबसे खास बात यह है कि अब मुझे किसी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। पूरा किराया मुझे मिल जाता है। इसमें 40 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान है। यह अन्य निजी टैक्सी कंपनियों के मुकाबले बहुत कम है। सरकार भी हमें अधिक से अधिक सहूलियत देने का प्रयास कर रही है। इसमें टैक्सी चालकों की सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। सभी को इससे जुड़कर लाभ उठाना चाहिए।

मेरा नाम पटनी किशनभाई है। मैं ऑटो ड्राइवर हूं और वर्ष 2012 से अहमदाबाद में ऑटो चला रहा हूं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में भारत टैक्सी का बाजार में आना ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत सुखद है। क्योंकि इसमें हम मालिक बनकर काम करेंगे और ड्राइवर से मिलने वाला पूरा किराया उनका होगा। निजी कंपनियों में हमें कमीशन देना पड़ता था। इसमें कमीशन से छुटकारा मिल गया और हमारी कमाई बढ़ गई। भारत टैक्सी के ऐप में कस्टमर की सुविधा और उसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। टैक्सी में यात्रा कर रहे कस्टमर अपने परिवार के संपर्क में रहेंगे। उसके परिजन घर बैठे उसे देख सकेंगे उनकी कुशल क्षेम जान सकेंगे।■

असम की प्रगति समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्रदान कर रही गति

सहकार जागरण टीम

- **हर क्षेत्र व हर वर्ग का विकास हमारी प्राथमिकता : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी**
- **एमएसपी, किफायती ऋण, फसल बीमा और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों के लिए बड़ा संबल बन गई हैं**

हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसी भावना के साथ, असम के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी पहल की गई है। यह उन्हीं की कड़ी मेहनत है जिसने दुनिया में असम की पहचान को मजबूत किया है। उनके द्वारा उगाई गई चाय की महक आज दुनिया भर में भारत की पहचान बन गई है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में एक लाख 94 हजार 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन और 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की किसान सम्मान निधि जारी करते हुए करते हुए कही। प्रसिद्ध निमाती घाट और बिश्वनाथ घाट पर आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाने का कार्य शुरू होने की घोषणा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस कदम से असम में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। सरकार ने पर्यटन को रोजगार और विकास के बड़े अवसर के तौर पर देखा है। इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर वॉटर टूरिज्म की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। एक बार क्रूज टर्मिनल बन जाने के बाद ब्रह्मपुत्र पर क्रूज का संचालन और आगे बढ़ेगा। इससे भारत तथा दुनिया भर के पर्यटकों के लिए असम पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। जैसे-जैसे क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, कारीगरों और हस्तशिल्प का काम करने वालों को नए बाजार मिलेंगे और छोटे दुकानदारों, नाव चलाने वालों, तथा होटल और परिवहन से जुड़े लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। असम में पर्यटन स्थानीय विकास और लोगों की समृद्धि का नया इंजन बन रहा है। असम भारत के पूर्वोत्तर–यानी 'अष्टलक्ष्मी' के नए भविष्य के लिए आदर्श के रूप में उभर रहा है। असम की प्रगति समूचे पूर्वोत्तर को नई गति प्रदान कर रही है। हमें 'विकसित असम' के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि असम देश में आदर्श राज्य के रूप में उभर सके।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि पूरे देश के करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में स्थानांतरित करने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस योजना को असाधारण बताया। अब तक ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में 4.25 लाख करोड़ से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। अकेले असम में ही लगभग 19 लाख किसानों को अब तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पिछले 11 वर्ष में देश के किसानों के चारों ओर मजबूत सुरक्षा कवच बुनने का जिक्र करते

श्री मोदी को मिला सबसे लंबे समय तक सरकार का मुखिया होने का गौरवः श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा मील का पत्थर हासिल किया है, जिसकी नींव सेवा, कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण पर टिकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में किसी भी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया है। सार्वजनिक जीवन के उनके 8,931 दिन–पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में 'राष्ट्र-प्रथम' शासन, कार्यों में ईमानदारी और प्रत्येक नागरिक की अथक सेवा के प्रति गहरे समर्पण को दर्शाते हैं। यह एक ऐसी दुर्लभ विरासत है, जो अभूतपूर्व विश्वास और बेजोड़ सेवा पर निर्मित है। उनकी दशकों की सेवा ने अपने आप में एक युग का निर्माण किया है।

श्री शाह ने कहा कि 'नए भारत' को गढ़ने के लिए जीवन भर प्रयास करने की जरूरत थी और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वह कर दिखाया। चाहे गरीबों को उनके अधिकार दिलाना हो, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करना हो, या वैश्विक मंचों पर राष्ट्र का गौरव बढ़ाना हो, मोदी युग ने भारत को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने कहा कि

24 वर्षों से भी अधिक समय तक बिना अवकाश लिए राष्ट्र और लोगों की सेवा करना श्री मोदी के अटूट समर्पण का ही एक प्रमाण है। श्री शाह ने कहा कि इसी वजह से प्रधानमंत्री श्री मोदी को लोगों से अभूतपूर्व स्नेह प्राप्त हुआ–तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उनके प्रति लोगों का विश्वास, स्नेह और समर्थन हर दिन बढ़ रहा है।

हुए श्री मोदी ने बताया कि एमएसपी, सस्ते ऋण हों, फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि आदि योजनाएं किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई हैं। सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि अंतरराष्ट्रीय संकटों का असर खेती-बाड़ी और कृषि पर न पड़े। यूरिया का एक कट्टा, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपए है, सरकार ने भारतीय किसानों को सिर्फ.300 रुपए में उपलब्ध कराया है। सरकार ने अपने खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, ताकि दुनिया भर में उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ हमारे किसानों पर न पड़े। खेती को नई प्रौद्योगिकी और किसानों को सिंचाई के नए तरीकों से जोड़ते हुए सरकार ने 'हर बूंद, ज्यादा फसल' की नीति अपनाई और किसानों तक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी माइक्रो-इरिगेशन टेक्नोलॉजी पहुंचाई। इससे सिंचाई में सुधार हुआ है और लागत भी कम हुई। सरकार अब खेतों को सोलर पंप से जोड़ने पर काम कर रही है। कई किसान न सिर्फ.सोलर पंप से सिंचाई कर रहे हैं, बल्कि बिजली भी बना रहे हैं और उसे बेचकर उससे पैसे भी कमा रहे हैं। खाद और कीटनाशकों पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा सरकार ने खाद फैक्टरियों को फिर से चालू किया है और किसानों को 'नैनो यूरिया' से जोड़ने के लिए कई पहल की हैं। किसानों को 'प्राकृतिक खेती' अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत की रिफाइनरियों के विकास और रिफाइनिंग क्षमता के विस्तार का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भारत ऐसा देश है जो न सिर्फ.अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। पिछले कुछ वर्ष में असम की रिफाइनरियों का भी विस्तार किया गया है। असम और समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैस पाइपलाइन अवसंरचना में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। नुमालीगढ़-सिलिगुड़ी पाइपलाइन का उन्नयन कार्य पूरा हो चुका है और असम के गोलाघाट में दुनिया का पहला 'सेकंड-जेनरेशन बायो-इथेनॉल प्लांट' लगाया गया है। यह नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना से न केवल असम, बल्कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाभ होगा। ये परियोजनाएं असम के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रही हैं और राज्य की समृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं।■

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के कुशल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन

देश के विकास का सशक्त इंजन बन रही सहकारिता

- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ किया विचार-मंथन**
- **सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में पैक्स कंप्यूटरीकरण, विकेंद्रीकृत भंडारण और सहकारी इकोसिस्टम को सशक्त बनाने पर जोर**

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने और सहकारिता क्षेत्र को अधिक सशक्त, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और जन-केंद्रित बनाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय निरंतर पहल कर रहा है। स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय के गठन के पिछले चार वर्षों के दौरान इस दिशा में सौ से अधिक महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं। साथ ही, सहकारिता नीति 2025 को लागू करके सहकारी क्षेत्र को देश के विकास के सशक्त इंजन के रूप में स्थापित करने की मुहिम को गति दी गई है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के कार्यान्वयन पथ एवं आगे की राह' विषय पर गहन मंथन किया गया। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कॉन्क्लेव में देशभर से नीति-निर्माताओं, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों एवं हितधारकों ने भाग लिया और सहकारिता नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से बहुकार्यात्मक इकाइयों में बदलने, 80,000 से अधिक पैक्स के कंप्यूटरीकरण, विश्व के सबसे बड़े सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना एवं युवाओं, महिलाओं व सहकारी समितियों के सदस्यों की शिक्षा पर जोर देने के साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों, क्रेडिट-बैंकिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे व्यापक विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता का अहम योगदान

सहकारिता के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने देश के विकास में सहकारी क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सहकारिता भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना का एक मजबूत स्तंभ रही है। दशकों से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण में सहकारिता ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में वर्तमान दौर की बढ़ती ग्रामीण आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है, जो विकसित हो रही हमारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप सहकारी विकास की एक व्यापक और दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत करती है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सक्षम मार्गदर्शन में यह नीति सहकारिता को देश के विकास के दूसरे इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। सहकारिता की नींव को सुदृढ़ करना, सहकारी ढांचे का विस्तार, व्यावसायिक इकोसिस्टम का विकास, पारदर्शी एवं पेशेवर प्रबंधन, सदस्य-केंद्रितता को बढ़ावा देना, नए कार्य क्षेत्रों में विस्तार और कोऑपरेटिव सेक्टर में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना हमारी सहकारी नीति के मुख्य आयाम हैं। उन्होंने कहा कि नई सहकारिता नीति का लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास को गति देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करना है। राज्यों को अपनी सहकारिता नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए श्री गुर्जर ने उन्हें सहकारिता आंदोलन को और गति देने को प्रेरित किया।

सहकारी क्षेत्र में दूरगामी सुधारों पर सरकार का फोकस

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुरूप अनेक दूरगामी एवं परिवर्तनकारी पहल किए हैं। इनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय आर्थिक इकाइयों में विकसित करना, पैक्स एवं एम-पैक्स को 25 से अधिक गतिविधियों में सक्षम बनाना, 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना, श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क तथा 'भारत टैक्सी' जैसी अभिनव पहलों का क्रियान्वयन शामिल है।

देश में 80 हजार से अधिक पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिससे उन्हें बहुउद्देशीय, व्यावसायिक और अधिक उपयोगी इकाइयों में परिवर्तित किया जा सके। हमारी कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर सरकार का फोकस है और इसके लिए पैक्स स्तर पर भंडारण का विकेंद्रीकरण कर इसे देश के कोने-कोने तक सुनिश्चित करते हुए ब्लॉक और तहसील स्तर तक विकसित किया जा रहा है। किसानों के फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना तथा लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

पैक्स को विकास के इंजन के रूप में सशक्त बनाने पर जोर

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान को तीन गुना करने की रणनीतियों पर बल देते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रो. एस. महेंद्र देव ने सम्मेलन में कहा कि सहकारिता समावेशी और सतत विकास का एक प्रभावशाली माध्यम बन सकती है। उन्होंने कहा कि सहकारिता समावेशी तथा सतत विकास का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। प्रो. देव ने सहकारिता को अर्थव्यवस्था का दूसरा इंजन बनाने की संभावना पर जोर दिया और समाज के अंतिम छोर तक ग्रामीणों को सस्ता ऋण पहुंचाने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सरकारिता की अहम भूमिका की सराहना की।

आगामी वर्ष तक हर गांव में होगी एक सहकारी समिति

श्री शाह ने विश्वास के साथ कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सहकारिता व्यवस्था बने और हम यह लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसी को ध्यान में रखकर नई सहकारिता नीति तैयार की गई है। हर गांव में एक कोऑपरेटिव संस्था बनाना इसका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सहकारिता 140 करोड़ देशवासियों के विकास की चाबी बने। जिन लोगों के पास पूंजी नहीं है लेकिन मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए सहकारिता ही एकमात्र रास्ता है। दलित, आदिवासी, महिलाएं सभी को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है। श्री शाह ने जोर देकर कहा, भविष्य की पीढ़ी के लिए यह कॉपरेटिव नीति तैयार की गई है। देश भर में मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे और समितियों की संख्या में 30 फीसदी की वृद्धि होगी। श्वेत क्रांति 2.0 में महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी। श्री शाह ने साफ कहा, 'यह एक ऐसी नीति है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान है और हर 10 साल में कानून में जरूरी बदलाव की भी व्यवस्था है। जब नई सहकारिता नीति को पूरी बारीकी से लागू किया जाएगा, तो भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश मराठे ने इस अवसर पर कहा कि सुदूर के गांवों तक अंतिम छोर के लोगों को किफायती ऋण सुलभ कराने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका सबसे अधिक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र विविध और जीवंत इकोसिस्टम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इससे ग्रामीण व समाज के कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं आसानी से पहुंच रही हैं। श्री मराठे ने सहकारिता आंदोलन को नई दिशा, नवाचार और मजबूती देने की दिशा में सम्मेलन की सार्थकता की सराहना की और सहकारी क्षेत्र को पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी एवं समावेशी विकास के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था के विकास में और अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया।

सहकारी सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पैक्स को विकास के इंजन के रूप में सशक्त बनाने, सदस्य शिक्षा, युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी, जैविक उत्पाद बाजार में नेतृत्व तथा सहकारी ऋण एवं बैंकिंग जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। ब्रेकआउट सत्रों और ओपन हाउस चर्चाओं के माध्यम से नीति के क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए तथा समापन सत्र में आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। सहकारी नीति के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर केंद्रित यह सम्मेलन निश्चय ही सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। ■

जीडीपी में सहकारिता का योगदान तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य

सहकार जागरण टीम

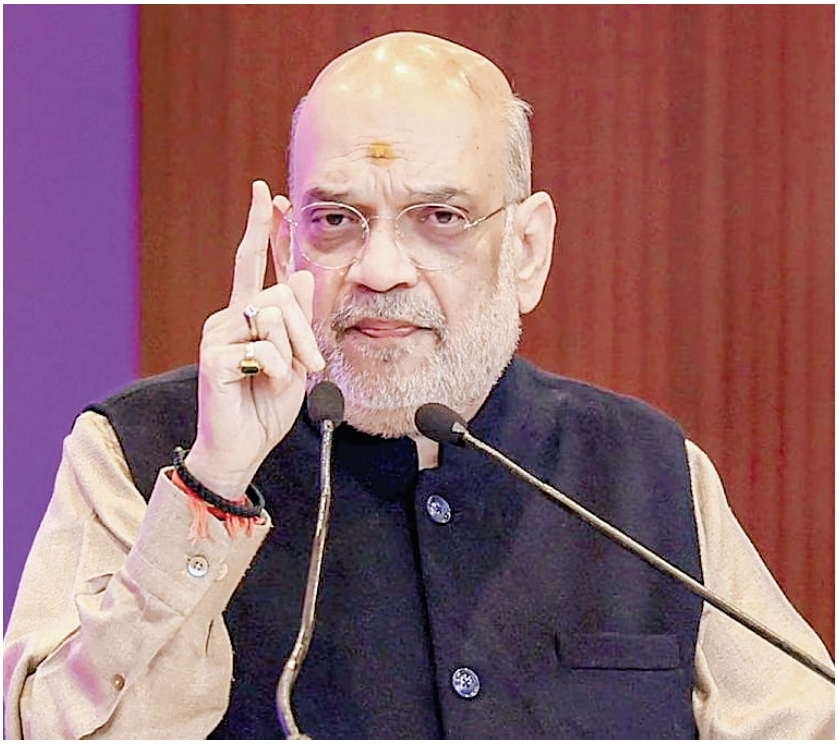

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने देश की जीडीपी में सहकारी क्षेत्र का योगदान वर्ष 2034 तक तीन गुना बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, 50 करोड़ नए नागरिकों को सहकारी क्षेत्र का सक्रिय सदस्य बनाने और सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने का संकल्प भी व्यक्त किया है। इसके लिए देश के प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक प्राथमिक सहकारी इकाई (जैसे पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन समिति) स्थापित करने की कवायद की जा रही है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पारदर्शिता, वित्तीय स्थिरता और संस्थागत विश्वास बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर और निगरानी तंत्र भी विकसित किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार सहकारी संस्थाओं को हर क्षेत्र में सहायता के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन इकाइयों को स्वयं को मजबूत करना होगा। जब सभी राज्य नई सहकारिता नीति को बारीकी से लागू करेंगे, तब देश में एक सर्वसमावेशी, आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी मॉडल बनेगा।

भविष्य की पीढ़ियों के लिए सहकारिता को देश के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाने के लिए अगले दो दशकों में तकनीक को हर छोटी से छोटी इकाई तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कंप्यूटरीकरण के माध्यम से कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन आएगा। श्री शाह ने में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह सहकारिता नीति ग्रामीण, कृषि इकोसिस्टम और देश के गरीब को अर्थतंत्र का विश्वसनीय हिस्सा बनाएगी। यह नीति दूरदृष्टिपूर्ण, व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी है, जिसका लक्ष्य 2047 में देश की आजादी की शताब्दी तक सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना है।

भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाने वाली नई सहकारिता नीति 2025 के निर्माण के दौरान ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नई नीति के माध्यम से देश के सभी गांवों तक सहकारिता को विस्तार देने और लोगों को इससे जोड़ने का संकल्प पूरा होगा। सहकारी क्षेत्र को सामयिक आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बहुआयामी बनाने के लिए ही सरकार ने नई सहकारिता नीति 2025 का निर्माण किया है। श्री शाह ने कहा, ''नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनने से 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी, देश में सहकारी आंदोलन सशक्त होगा और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक होगी।'' उन्होंने कहा कि भारत का मूल विचार एक ऐसा मॉडल बनाने का है जिसमें सबका सामूहिकता के साथ विकास हो, और सभी के योगदान से देश का विकास हो। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता नीति व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद तैयार की गई, जिसमें 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति ने 17 बैठकों और चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से देशभर के सुझावों को शामिल कर उसपर अमल किया।■

देश में समग्र सहकारी विकास का बन रहा ईको सिस्टम

सहकार जागरण टीम

- 33,853 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियां (एम-पैक्स), डेयरी और मात्स्यिकी समितियां पंजीकृत
- पहले से मौजूद 21,292 डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है

देश में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा, गति और विस्तार देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय ने अबतक सौ से अधिक ठोस नीतिगत और व्यावहारिक पहल किए हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के उद्देश्यों के अनुरूप देश में समग्र सहकारी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई इन पहलों के सफल कार्यान्वयन और उनके प्रभाव की निगरानी के लिए भी विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है। इन पहलों के सुचारू और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर मौजूद अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 33,853 नए बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियां (एम-पैक्स), डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं और 21,292 डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है। सभी सहकारी पहलों के सुचारू और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सक्रिय रूप से संबद्ध किया गया है।

सहकारी संस्थाओं को मजबूत, पारदर्शी और बहुपयोगी बनाने वाली इन योजनाओं और बहुआयामी पहलों की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्च स्तरीय निगरानी भी सुनिश्चित किया है। इसके लिए प्रत्येक महीने सहकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही, राज्यों के सहकारी विभागों के प्रधान सचिवों, सचिवों और राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ भौतिक रूप से प्रत्येक तीन महीने की समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में पिछले दिनों राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता मंत्रियों और सभी हितधारकों के साथ 'मंथन बैठक' का आयोजन इस दिशा में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति के अन्तर्गत छह रणनीतिक स्तंभ सुनिश्चित किए गए हैं। इनमें से एक समावेशिता को बढ़ावा देने और सहकारिता की पहुंच को सघन करने पर केंद्रित है। इसका ध्येय सहकारी आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है। सहकारिता के माध्यम से समाज में समावेशिता को बढ़ावा देने और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के लिए ठोस पहल करते हुए महिलाओं, युवाओं, लघु और सीमांत किसानों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व दिव्यांगजन आदि समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सहकारी समितियों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मात्स्यिकी, डेयरी, हथकरघा बुनाई, हस्तशिल्प और लघु वनोत्पाद आदि क्षेत्रों में कमजोर और सीमांत वर्गों के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त करने के प्रावधान किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में महिलाओं और कमजोर वर्गों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में उन्हें शामिल करने की अनुशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय ने डेयरी क्षेत्र में सहकारी कवरेज के विस्तार, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण के लिए सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध संग्रह करने की क्षमता को दोगुना करना है।■

सहकारिता क्षेत्र के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

सहकार जागरण टीम

देश में सहकारिता क्षेत्र हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण का आधार बन रहा है जिससे समाज के सामूहिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। सहकारी आंदोलन को देश के सभी हिस्सों और गांवों में सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सघन करने की सहकारिता मंत्रालय की पहल पर दो लाख नई मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में 32,802 नई समितियां स्थापित की गई हैं, जिनमें 8,710 नए बहुउद्देशीय पैक्स, 21,982 बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियां (एमडीसी) और 2,110 बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियां (एमएफसी) शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक 5,925 नई बहुद्देशीय सहकारी समितियों को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। वहीं, बिहार में 4,648, राजस्थान में 3,583, ओडिशा में 2,281, मध्यप्रदेश में 1,763, जम्मू और कश्मीर में 1,565, महाराष्ट्र में 1,450, कर्नाटक में 1,385, गुजरात में 1,254, छत्तीसगढ़ में 1,142, असम में 1,141, आंध्रप्रदेश में 1,047 और उत्तरखंड में 1,004 नई बहुदेशीय सहकारी समितियों को स्थापित किया है। सहकारी सेवाओं में विविधता और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने वाली इन समितियों के गठन के माध्यम से ग्रामीण विकास और लोगों के सामाजिक-आर्थिक उन्नति में सहकारिता की भागीदारी बढ़ रही है।

- **देश में 32 हजार से अधिक नई बहुद्देशीय सहकारी समितियों का गठन**
- **8,710 नए बहुउद्देशीय पैक्स, 21,982 बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियां (एमडीसी) और 2,110 बहुउद्देशीय मत्स्य सहकारी समितियों का गठन**
- **इन समितियों के गठन से ग्रामीण विकास और लोगों के सामाजिक-आर्थिक उन्नति में सहकारिता की बढ़ रही भागीदारी**

प्रत्येक गांव में होंगी सहकारी समितियां

सरकार का लक्ष्य देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को बढ़ाने के साथ ही सभी पंचायतों व गांवों तक वित्त वर्ष 2027-28 तक नई बहुद्देशीय पैक्स, प्राथमिक डेयरी या मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करना है। इस योजना में डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना निधि (एफआईडीएफ) सहित सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के प्रसार पर जोर दिया गया है। यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी),

सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर फोकस

सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के संचालन में दक्षता बढ़ाने, किसानों को ऋण वितरण को तेज करने, लेन-देन की लागत कम करने और भुगतान में असंतुलन घटाने साथ ही सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने इस परियोजना के लिए 2,516 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पैक्स परियोजना के कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को पूरा करना और किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की सेवा प्रदाय को मजबूत करना, इन संस्थानों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के लिए पैक्स के कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम और राष्ट्रव्यापी एकरूप मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (एमआईएस) में प्रवास की सुविधा प्रदान करना है। इस परियोजना के अंतर्गत, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) की कोर बैंकिंग प्रणालियों (सीबीएस) के साथ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर पैक्स के एकीकरण की परिकल्पना की गई है।

कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़े हैं 13 करोड़ किसान

हमारे देश में लगभग 63,000 से अधिक पैक्स पहले से कार्यशील हैं और नए बहुद्देशीय पैक्स को मिलाकर इनकी संख्या करीब 80,000 हो गई है। ये सहकारी समितियां करीब 13 करोड़ किसानों की सेवा करती हैं। ग्रामीण स्तर पर सहकारिता की सबसे बुनियादी इकाई के रूप में सक्रिय पैक्स छोटे और सीमांत किसानों को अल्पकालिक ऋण, बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि उपलब्ध कराते हैं। सरकार की पहल से पैक्स अब बहुउद्देशीय हो रहे हैं और किसानों को ऋण प्रदान करने के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), अन्न भंडारण, उर्वरक व बीज वितरण, मार्केटिंग, बीमा और प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र आदि के रूप में 25 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे किसानों को आसान, तेज और पारदर्शी सेवाएं मिलना सुनिश्चित हुआ है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। सरकार पैक्स को पंचायत स्तर पर नोडल डिलीवरी पॉइंट बना रही है, जिससे किसानों को ऑनलाइन लेखांकन, त्वरित ऋण सुविधा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल रहा है और सहकारी संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इसप्रकार, यह योजना आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघों और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कार्य समितियों का गठन

सहकारी विकास की इस बहुआयामी योजना के सुचारू और एकरूप कार्यान्वयन के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) जारी की गई है जिसमें लक्ष्यों, समय-सीमा, संस्थागत संरचना और हितधारकों की भूमिकाओं का तय की गई है। राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों और संबंधित एजेंसियों को शामिल करते हुए एक बहु-स्तरीय संस्थागत संरचना स्थापित की गई है और इसके तहत केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों व विभागों के मंत्रियों व सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। इस पहल के समग्र कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों व विभागों के सचिवों और अन्य संबंधित हितधारकों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए राष्ट्र स्तरीय समन्वय समिति (एनएलसीसी) का गठन किया गया है।

राज्यों के स्तर पर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) और जिला स्तर पर इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) का गठन किया गया है। इसके साथ ही, जमीनी स्तर पर इस योजना का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों ने जिला स्तर पर संयुक्त कार्य समितियों का भी गठन किया है।

पैक्स कंप्यूटरीकरण के सॉफ्टवेयर का अन्य राष्ट्रीय पोर्टल से एकीकरण

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को डिजिटल बनाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए बताया कि इसी उद्देश्य से सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी आधारित एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़कर नाबार्ड के माध्यम से इसे राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से लिंक किया जा रहा है। ईआरपी सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस या अन्य सरकारी पोर्टलों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके), प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) आदि से लिंक किया जाएगा। सॉफ्टवेयर को अन्य राष्ट्रीय पोर्टलों (जैसे पीएम-किसान, डीबीटी आदि) से एकीकृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के साथ एकीकरण पूरा हो गया है और कॉमन सर्विस केंद्र (सीएससी) और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के साथ एकीकरण कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।■

विश्वास, सहभागिता और सामूहिक प्रगति का सशक्त जन आंदोलन है सहकारिता

सहकार जागरण टीम

ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को संगठित कर त्रिपुरा की गोमती सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था 'सहकार से समृद्धि' की भावना को साकार कर रही है। यह संस्था प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का मूर्त उदाहरण है। ऐसी सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण एवं विस्तार के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय विशेष प्रयास कर रहा है।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने इन विचारों को पूर्वोत्तर के त्रिपुरा राज्य में गोमती सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह डेयरी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली एक सफल सहकारी व्यवस्था है। इस डेयरी कोऑपरेटिव के दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण, वितरण और अन्य डेयरी उत्पादों के निर्माण की कार्यप्रणाली पर जोर देते हुए श्री मोहोल ने कहा कि कोऑपरेटिव की अवधारणा केवल आर्थिक लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सहभागिता और सामूहिक प्रगति की एक सशक्त जनआंदोलन है। सहकारी क्षेत्र के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। उन्होंने कहा कि श्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित किए गए स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने पिछले वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं और सहकारिता के जरिए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर अभिनव पहल किए जा रहे हैं।

संसाधन और क्षमता संपन्न त्रिपुरा राज्य में डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की अपार संभावनाएं हैं। भारत

डेयरी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली एक सफल सहकारी व्यवस्था है गोमती सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था

सरकार ने राज्य के साथ मिलकर पिछले वर्ष पश्चिमी त्रिपुरा जिले के बामुतिया में गोमती सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के 40 हजार लीटर प्रति दिन क्षमता वाले गोमती यूनिट-2 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर भारत के इस सबसे बड़े डेयरी संयंत्र के निर्माण में केंद्र सरकार ने 19 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने दो करोड़ रुपए का योगदान दिया। यहां 10,000 लीटर दूध का उपयोग दही, पनीर, आइसक्रीम और लस्सी जैसे उत्पादों के लिए किया जा रहा है। इस नई सुविधा से त्रिपुरा के डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ही अन्य राज्यों से दूध आयात पर निर्भरता कम हुई है और इसने स्थानीय दूध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। अब यह संस्था जीबी अस्पताल, आईजीएम अस्पताल, बीएसएफ, सेना और सीआरपीएफ को भी दूध की आपूर्ति कर रही है।

पूर्वोत्तर में डेयरी विकास को नई दिशा दे रही गोमती सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष रतन घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वर्ष 1982 में स्थापित गोमती सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था से वर्तमान में 6,200 से अधिक दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं तथा 183 दुग्ध डेयरियां इससे संबद्ध हैं। पश्चिम त्रिपुरा क्षेत्र में 40 दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से 12 दुग्ध वितरण केंद्रों से चार विभिन्न श्रेणियों में दूध का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही, दो प्रकार का पनीर, 13 प्रकार की आइसक्रीम और 73 प्रकार की मिठाइयों सहित विविध दुग्धजन्य उत्पादों का निर्माण भी किया जा रहा है। यहां गाय के शुद्ध दूध से उच्च गुणवत्ता वाले घी का भी उत्पादन किया जाता है। राज्य की पहल पर गोपालकों को पांच हजार रुपए का अनुदान और डेयरी विकास अधिकारियों के माध्यम से गाय खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

हजारों परिवारों के रोजगार और समृद्धि का आधार बनी सीताजाखला डेयरी कोऑपरेटिव

सहकार जागरण टीम

सहकारिता का मॉडल सामुहिक उन्नति की ऐसी राह दिखाता है जिसमें छोटे स्तर से शुरू करके भी संगठित प्रयास से बडी उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। असम की सीताजाखला डेयरी समिति की सफलता भी एक ऐसी ही कहानी बयां करती है जिसने न सिर्फ दूध और डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराने और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम किया है, बल्कि हजारों परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और समृद्धि का साधन देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। पशुपालन सुधार, किसान सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यह एक मिसाल है। समिति के उत्थान से किसानों की आय स्थिर हुई है, क्योंकि वे मध्यस्थों के शोषण से मुक्त होकर अपने डेयरी उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

मध्य असम के मोरीगांव जिले के जगीरोड के अमलीघाट गांव के 17 किसानों ने 1958 में सीताजाखला दुग्ध उत्पादक समबाई समिति लिमिटेड का गठन कर उपरोक्त पहल की। वर्तमान में समिति के सदस्यों की संख्या बढ़कर एक हजार से अधिक हो चुकी है। अपने गठन के 67 साल पूरे कर चुकी समिति असम के गुवाहाटी, कामरूप, मोरीगांव और नागांव जिलों में सक्रिय है। यह इन जिलों के 122 ब्लॉकों से दुग्ध उत्पादकों से दूध संग्रहित करती है। समिति के पास 11 दूध संग्रह केंद्र और दो प्लांट हैं। एक दूध के लिए और दूसरा दही के लिए। एक समय सीताजाखला के संयंत्र की कुल क्षमता 18000 लीटर प्रति दिन थी, लेकिन अब यह 12000 लीटर प्रतिदिन हो गई है।

नेपाली समुदाय के किसान नंदलाल उपाध्याय जैसे व्यक्तियों की पहल से यह डेयरी कोऑपरेटिव 'श्वेत क्रांति' की दिशा में आज असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रेरणादायक मॉडल बन गया है। शुरू में छोटे स्तर पर शुरू हुई यह समिति आज पाश्चुरीकृत दूध, दही, घी, पनीर जैसी मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों का उत्पादन और विक्रय करती है। यह सहकारी समिति हजारों परिवारों की आजीविका का आधार बनी हुई है।

वैसे तो इससे सीधे तौर इससे पर एक हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक किसान जुड़े हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह चार हजार से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाती है, जिसमें दूध संग्रह, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, वितरण और अन्य गतिविधियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है। इस समिति किसानों को मुफ्त में डेयरी फार्मिंग संबंधी सेवाएं, जैसे-पशु चिकित्सा, फीड, प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे दूध की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ती है। यह समिति सामाजिक योगदान भी कर रही है और इसने अपनी कमाई से स्थानीय स्कूल चलाने में मदद की। 2007 में यह सरकारी स्कूल घोषित हुआ, लेकिन उच्च कक्षाएं लंबे समय तक समिति के सहयोग से चलीं।

समिति गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। यह उन्हें बेहतर नस्ल के गोवंशों का सीमेन उपलब्ध कराने में मदद कर रही है और गायों द्वारा केवल मादा बछड़ों को जन्म देने की सुविधा प्रदान कर रही है। गायों को पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए समिति ने भंडारण की स्थापना करने की योजना भी बनाई है। योजना को अमल में लाने के लिए भंडारगृह बनाए जा रहे हैं। गायों को बीमारी से बचाने के लिए यह उनका मुफ्त टीकाकरण करती है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए किसानों को जागरूक किया जाता है। समिति गो-पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी करती है व उनके समुचित पोषण की जानकारी देती है, ताकि गायें अधिकतम दूध प्रदान कर सकें। इसके अलावा समिति की ओर से मक्का की खेती और खनिज मिश्रण संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को वित्तीय सहायता और अन्य आवश्यक मदद प्रदान करने की भी योजना बनाई जा रही है।

असम के चार जिलों में सीताजाखला एक ब्रांड बन चुका है। पशुओं के चारे की खरीद-बिक्री में भी शामिल समिति स्थानीय युवाओं को रोजगार देती है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। सीताजाखला दुग्ध उत्पादक समाबाई समिति लिमिटेड असम के हजारों परिवारों को जोड़कर उनके लिए रोजगार का अवसर प्रदान कर रही है। समिति का सालाना टर्नओवर 16 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है।

समिति की कार्यप्रणाली फार्म टू टेबल मॉडल पर आधारित है। कारोबार से बिचौलियों की भूमिका खत्म कर किसानों को बेहतर दाम व उपभोक्ताओं को ताजा उत्पाद उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है और काफी हद तक यह अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल है।■

विशेष आलेख

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव

सहकारी नीतियों को लागू करने में समितियों की बड़ी भूमिका

भारत में बहुआयामी विकास कार्यों के साथ ही कृषि क्षेत्र का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना और आत्मनिर्भरत भारत के लक्ष्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय निरंतर पहल कर रहा है। सरकारी सहायता और वित्तीय-सुविधाओं के माध्यम से जहां एक ओर कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिल रही है, वहीं तकनीक और नवाचारों के प्रयोग के प्रति किसानों में जागरूकता फैलाने में सहकारी समितियों की भागीदारी भी तेज हो गई है। देश में सहकारिता के तेजी से हो रहे विस्तार और विकास के साथ आधुनिक संसाधनों से अधिक कार्यक्षम हो रहीं सहकारी समितियां अब सिर्फ इनपुट वितरण के लिए चैनल नहीं हैं, बल्कि वे सिस्टम परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक भी हैं। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से सक्षम और संसाधनयुक्त होकर ये सहकारी समितियां नीतिगत आकांक्षाओं को पूरा करने और किसानों की समृद्धि की राह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हो रहीं हैं। भारत की कृषि सहकारी समितियां, जिन्हें पहले ग्रामीण विकास के मौन कार्यकर्ता के रूप में माना जाता था, भारत की कृषि रसायन आपूर्ति शृंखला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इफको व कृभको जैसी शीर्ष संस्थाएं सहकारी समितियां उत्पादकों और किसानों के बीच की उस गहरी खाई को पाट रही हैं, जिसे पारंपरिक बाजार मध्यस्थ उचित रूप से भरने में असमर्थ रहे हैं।

ये कृषि-सहकारी संस्थाएं स्थानीय वितरण नेटवर्क, थोक खरीद और प्रत्यक्ष किसान भागीदारी का उपयोग करके सहकारी समितियों को सरकारी नीतियों को व्यवहार में लाने में सक्षम बनाती हैं। गांवों तक फैले अपने स्थानीय नेटवर्क और परिचालन अनुकूलनशीलता के साथ सहकारी समितियां ग्रामीण किसानों के जीवन में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम हैं।

सहकारी समितियों की स्थानीय जड़ें उन्हें एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में ग्रामीण किसानों को सहयोग प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। ये समितियां किसानों को न केवल कृषि के लिए आवश्यक इनपुट उत्पाद प्रदान करती हैं, बल्कि सलाह, प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, इफको भारत में 36,000 से अधिक सहकारी समितियों का संचालन करती है, जो उर्वरक, कीटनाशक और यहां तक कि तरल नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी जैसी नैनो-आधारित तकनीक वितरित करती हैं। इसके अलावा कृभको कृषि रसायन और जैव-उर्वरक वितरित करने के लिए अपनी आपूर्ति शृंखला का उपयोग करता है और किसान शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है। ये संगठन केवल वितरक नहीं हैं, बल्कि वे क्षमता निर्माता भी हैं।

सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मॉडल में बदलाव के लिए मजबूत डेटा सिस्टम, डिजिटल साक्षरता पहल और अंतर-मंत्रालयी समन्वय पर फोकस किया है और ऐसी प्रणाली विकसित होने से लीकेज को कम कर किया गया है और सेवाओं की समयबद्धता सुनिश्चित हो रही है। सूचना साझा करने में सहकारी समितियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी है। देश के किसानों को सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं, एकीकृत कीट प्रबंधन कौशल और उभरती हुई नई कृषि रसायन तकनीकों के बारे में समय-समय पर सूचनाएं प्रदान करने के लिए सहकारी समितियां विशेष योगदान कर रही हैं और मोबाइल ऐप, प्रिंट सलाह और प्रदर्शनों के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का प्रचार-प्रसार कर रही हैं। समितियों से आवश्यक सुविधाएं,सहयोग और सरकार की नीतिगत सूचनाएं पाकर किसान खेतों में अधिक पैदावार का लाभ उठाकर समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही, ऋण और फसल बीमा सेवाओं और इनपुट की पैकेजिंग करके सहकारी समितियां किसानों की लागत कम करती हैं और उन्हें खेती में नुकसान के जोखिम से बचाती हैं।

दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहीं सहकारी समितियों की क्षमताओं को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। ब्लॉकचेन सक्षम आपूर्ति शृंखलाएं, मोबाइल ऑर्डरिंग एप्लिकेशन और वास्तविक समय शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म जैसे उपकरण ने बड़े पैमाने पर ग्रामीणों का विश्वास हासिल किया है और इससे पारदर्शिता के साथ सहकारी सेवाओं को विस्तार मिला है। सहकारिता मंत्रालय के सहकारी क्षेत्र में मानव क्षमता के विकास को प्राथमिकता देने से सहकारी कर्मियों के लिए आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता और कृषि रसायन साक्षरता प्रशिक्षण से सेवा गुणवत्ता वितरण में तेजी आ रही है और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। सहकारी समितियों के जैव-उर्वरक, एकीकृत कीट प्रबंधन किट और अन्य टिकाऊ इनपुट की आपूर्ति करने से देश में किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने में उत्साहजनक सहयोग मिल रहा है, जिससे सरकार के 'सहकार से समृद्धि' की आकांक्षा के साकार करने में मदद मिल रही है। ■

अध्यक्ष, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (आईसीए), एशिया-पैसेफिक

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत देश की एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अध्यक्षों और निदेशकों ने नई दिल्ली में कृभको और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जाकर कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को मजबूत करने में उनकी भूमिका की जानकारी हासिल की। एनसीयूआई की डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती दीप्ति यादव ने भी प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया।

राष्ट्रीय सहकारी संस्थानों की भूमिका, काम-काज और गवर्नेंस के बारे में जानने के लिए तमिलनाडु के द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के 21 छात्रों ने नई दिल्ली आकर एनसीयूआई का भ्रमण किया, जहां एनसीयूआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राजीव शर्मा ने सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद की विभिन्न पहलों की जानकारी दी। कोबी के प्रबंध निदेशक डॉ. वी. के. दुबे ने भी कोऑपरेटिव पॉलिसी पर चर्चा की।

नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन (एनसीसीई), नई दिल्ली ने बैंकर्स इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ के साथ मिलकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत से 38 कोऑपरेटिव लीडर्स एक साथ आए। एनसीयूआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राजीव शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती दीप्ति यादव, कोऑपरेटिव सर्विसेज (बीबीएसएसएल) के हेड श्री जे.पी. सिंह व एनसीईएल के अधिकारियों ने उनका ज्ञानवर्धन किया।

एनसीसीई ने बैंकर्स इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ के साथ मिलकर लेबर कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया के निदेशकों के लिए नई दिल्ली में तीन दिवसीय लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया। एनसीयूआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राजीव शर्मा व डिप्टी डायरेक्टर श्री अनंत दुबे, एनसीडीसी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और सहकार टैक्सी के वाइस चेयरमैन श्री रोहित गुप्ता और कोऑपरेटिव लेबर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक श्री वी. के. चौहान ने समितियों के डिजिटलीकरण, कोऑपरेटिव्स में आईटी के इस्तेमाल पर जोर दिया।

एनसीयूआई ने एनसीसीई, नई दिल्ली में ऑर्गेनिक खेती पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 20 प्रतिभागियों ने भागीदारी की, जहां पारंपरिक खेती की जगह ऑर्गेनिक खेती के लाभों, इसके लिए वित्तीय मदद और स्कीम, सर्टिफिकेशन प्रोसेस, मार्केट लिंकेज और निर्यात की संभावनाओं आदि विषयों पर जानकारी साझा की गई। एनसीयूआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राजीव शर्मा ने कोऑपरेटिव मॉडल को मजबूत करने में संस्थान की भूमिका की जानकारी दी।

एनसीयूआई ने 'कोऑपरेटिव और रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के सीईओ और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कोऑपरेटिव गवर्नेंस' विषय पर तमिलनाडु के जीआरई में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें इन दोनों संस्थाओं के साथ 'कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र' भी भागीदारी रहा। इसमें भारतीय संस्थाओं के सात पदाधिकारियों के साथ श्रीलंका के 19 और नेपाल के तीन प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और सहकारी वित्तीय संस्थानों में नेतृत्व को मजबूत करने की बारीकियों को परस्पर साझा करते हुए अपना ज्ञानवर्धन किया।

विकसित भारत के विकसित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट छह गुणा से अधिक बढ़ाया गया है। इन वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए हैं, एक लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 तक रेलवे में सिर्फ 20 हजार किलोमीटर रूट का बिजलीकरण हुआ था, जबकि 2014 के बाद से 40 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग शत-प्रतिशत बिजलीकरण हो चुका है। कश्मीर घाटी हो या नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां, ये पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही हैं। बंदरगाहों की क्षमता बीते दशक में दोगुने से अधिक हुई है। देश में नदी जलमार्गों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।

-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

NCUI हाट

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (**CEAS-LMS**) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

HINDI

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक: राजीव शर्मा

RNI No.: DLHI/25/A0141

Published on 11.05.2026 | Postal Registration No DL-SW-01/4214/2023-24

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ